

RNI NO: UPHIN/2015/64581

हिन्दी मासिक पत्रिका

पंचायत ग्राउन्ड जीरो से

₹ 30/- 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026

वर्ष - 12, अंक 119

सम्पूर्ण राजनीतिक पत्रिका



बीजेपी के बाँस



प्रति वर्ष 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन

गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू,
शीरा उत्पादन में अग्रणी



करके दिखाए जो
डबल इंजन
सरकार है वो

[▶ UPGovtOfficial](#) [f CMUttarpradesh](#) [✕ CMOfficeUP](#)



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

हिन्दी मासिक पत्रिका

पंचायत ग्राउन्ड जीरो से

₹ 30/- 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026

वर्ष - 12, अंक 119

सम्पूर्ण राजनीतिक पत्रिका

प्रधान संपादक
संजय कुमार सिंह

कार्यकारी संपादक
आनंद मिश्रा

प्रमुख सलाहकार
ई. जगमोहन गुप्ता

ब्यूरो प्रमुख
पंकज तिवारी - (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब)
ब्रजेन्द्र सिंह - (उ०प्र०, म०प्र०, राजस्थान)
राणा रणधीर सिंह (मध्य उ०प्र०)

आर.टी.आई. विशेषज्ञ
संतोष दुबे

डिजाइन एंड ग्राफिक्स
सतीश प्रजापति

डिजिटल विभाग
रिचा धिमान (वेब उप संपादक)

विशेष संवाददाता एवं फोटो डिपार्टमेंट
शिवम मिश्रा, अंकज तिवारी

विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें: 09918336644



पंचायत ग्राउन्ड जीरो से

RNI No: UPHIN/2015/64581

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी एवं संपादक संजय कुमार सिंह के पक्ष में ज्योति इंटरप्राइजेस 11 ई छेदी सिंह का पुरवा, बर्सा-2 से मुद्रित 992 एसबीआई कालोनी रतन लाल नगर से प्रकाशित ।

प्रधान संपादक

संजय कुमार सिंह

Web Portal:
www.groundzerose.com

E Magazine:
www.panchayatgroundzerose.com

कैम्प कार्यालय नई दिल्ली:- 13/5, माइल्स स्टोन, कापसखेड़ा

बॉर्डर दिल्ली-110037, मो.: 9999092568

कैम्प कार्यालय लखनऊ:- ओमेक्स रेसिडेंसी 1, नियर शहीद पथ,

गोमती नगर एक्टेन्सन, लखनऊ-226002

मो.: 9415051730, 9918336644

डाक पंजीकृत संख्या: 276/2015/2017

Contact No:

09918336644, 9415051730

Email:

panachayatgroundzerose@gmail.com



Our Youtube Channel:

panachayatgroundzerose

लेखक के विचारों से संपादक

का सहमत होना जरूरी नहीं है.

किसी भी प्रकार के विवाद के मामले

का न्यायिक क्षेत्र कानपुर न्यायालय

ही होगा

पेशा नहीं पत्रकारिता..



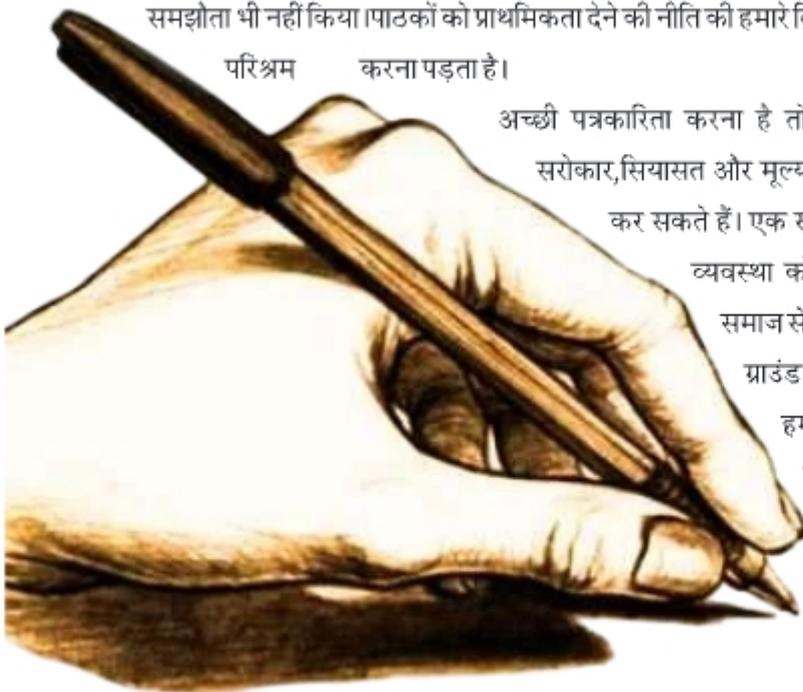
जब कलम डर से मुक्त होती है, तभी सच्ची पत्रकारिता जन्म लेती है। पत्रकारिता साधारण घटना नहीं है। संवाद आत्मा से होता है और आत्मा का ही होता है। आत्मा की अभिव्यक्ति आत्मा तक पहुंचेगी। सच्ची पत्रकारिता सत्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ प्रश्न पूछने की भावना पर आधारित होनी चाहिए। सच्ची और नैतिकतापूर्ण पत्रकारिता समाज और सरकार के लिए दर्पण का काम करती है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है, जो समाज के अभावों व कठिनाइयों को सामने लाता है और समाज को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के प्रति सजग करता है। वहीं समाज की पीड़ा और समाज के चिंतन के प्रति सरकार को आगाह कर उसे सामाजिक समस्याओं के समाधान के प्रति जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी भी पूरा करता है। जिस तरह लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा है, उसी तरह मीडिया भी जनता के लिए है। आप जैसा चाहेंगे, मीडिया वैसा ही चलेगा। आप इसकी चाबी अपने पास रखें। सबकी चाबी जनता/पाठक के पास है। हमारे मीडिया समूह का स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र के तीन ही स्तंभ हैं, मीडिया यदि चौथा स्तंभ बनने का प्रयास करेगा तो वह सरकार का भाग बन जाएगा, जिसका नुकसान जनता को होगा। मीडिया का काम लोकतंत्र के इन स्तंभों पर नजर रखते हुए उन्हें सकारात्मक दिशा दिखाना है। सरकार का भाग बनने पर मीडिया की जनता और सरकार के बीच सेतु की भूमिका समाप्त हो जाएगी। यहां जनता और पाठक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

“पंचायत ग्रांड जीरो से” पत्रिका के लिए पाठक ही सर्वोपरि है। यह पत्रिका पाठकों के विचार, भावनाएं, समस्याएं, चुनौतियां, अभावों का सदा ध्यान रखती है। दूरदराज के गांवों के वंचितों की आवाज भी यह पत्रिका बन रही है। निर्भीक होकर, बिना भय के अपनी नैतिक बात रखना हमारी जिम्मेदारी है। “पंचायत ग्रांड जीरो से” पत्रिका सरकार या व्यावसायिक घरानों के प्रति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पत्रिका की जिम्मेदारी तो केवल पाठकों के प्रति है। कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस पत्रिका ने अपनी नैतिकता और निष्पक्षता नहीं छोड़ी और कभी समझौता भी नहीं किया। पाठकों को प्राथमिकता देने की नीति की हमारे लिए सर्वोपरि है और सदा रहेगी। पत्रकारिता में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है।

अच्छी पत्रकारिता करना है तो वृहद ज्ञान की आवश्यकता है, सारे सिस्टम, जन सरोकार, सियासत और मूल्यांकन यदि सबका ज्ञान हो तभी आप अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं। एक सच्चे पत्रकार का फ़र्ज़ सिर्फ रिपोर्टिंग करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को जवाबदेह बनाना भी होता है। पत्रकारिता बहुत बड़ी समाज सेवा है। हमें यह सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि “पंचायत ग्रांड जीरो से” मीडिया समूह आपको मौका दे रहा है कि आप हमारे साथ जुड़कर पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बनाएं।

संजय सिंह

पंचायत ग्रांड जीरो से, के प्रधान संपादक
(चुनावी विश्लेषक एवं रणनीतिकार)



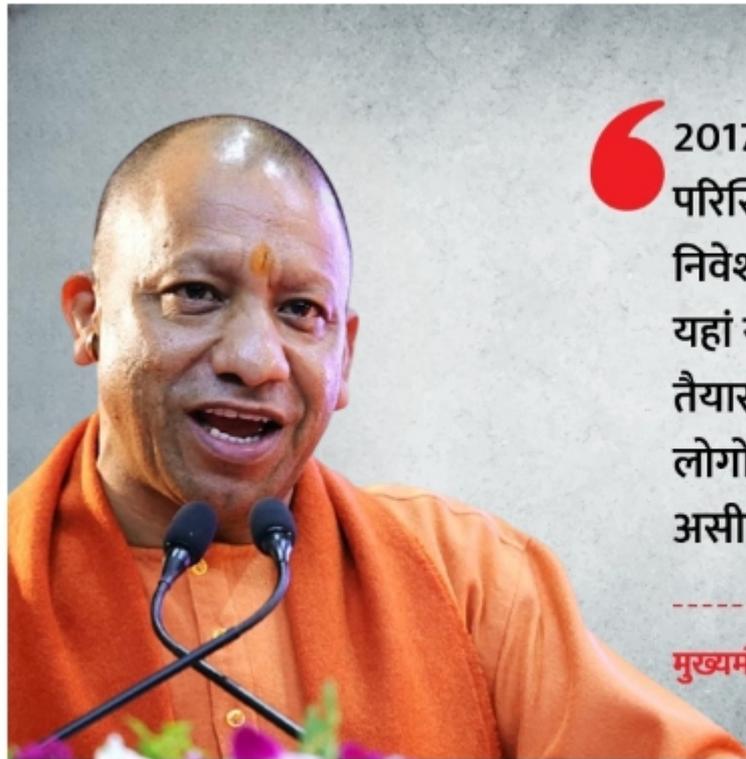
असीमित है यूपी CM योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते आठ वर्षों में यूपी सिर्फ असीमित क्षमताओं वाला प्रदेश ही नहीं रहा बल्कि क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज निवेशकों की पसंद में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले यूपी पहचान का मोहताज था, लेकिन आज यूपी उत्सव का प्रदेश है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। “फियरलेस बिजनेस”, “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” और “ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस” नई यूपी की पहचान बन चुकी है।

सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी देश की जीडीपी में 9.5 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। यूपी की जीएसडीपी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 36 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। लक्ष्य है कि 2029-30 तक यूपी वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने। सीएम योगी ने बताया कि दिसंबर 2023 में एमओयू हुआ, जनवरी 2024 में भूमि हस्तांतरण हुआ और मात्र 18 महीने में यह EV व्हीकल प्लांट बनकर तैयार हुआ, जो डबल इंजन सरकार की फास्ट ट्रैक प्रणाली का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में यूपी की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत रही। यूपी में वर्तमान में

700 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 का उल्लेख करते हुए कहा कि यूपी आज देश-दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है।

पिछले 8-9 वर्षों में यूपी में 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। यूपी अब अनलिमिटेड पोटेंशियल यानी संभावनाओं का परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन गया है। पिछले आठ-साढ़े आठ वर्षों में हुआ परिवर्तन इसका उदाहरण है। यह समारोह प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेश हो रहा है। देश के एक्सप्रेसवे का 55 प्रतिशत यूपी में है। देश में सर्वाधिक शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और मेट्रो का संचालन यूपी में हो रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी यूपी के पास है। इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी जी जिस तरह से यूपी को चला रहे हैं। उससे सहज ही प्रदेश की रेटिंग एक्सीलेंट कही जा सकती है।



2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थितियां थीं? अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर जो निवेश था वह भी यहां से पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने उस समय कहा था कि उत्तर प्रदेश असीमित क्षमताओं का प्रदेश है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

अशोक लीलैंड कंपनी की इस ईवी फैक्टरी का उद्घाटन प्रदेश के औद्योगीकरण की दिशा में मील का पत्थर है। पहले जिस यूपी को खराब कानून व्यवस्था और दंगों से जोड़कर देखा जाता था वो अब निवेश के क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। प्रदेश में निवेश होने से यहां के युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिल सकेगा। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। अब भारत एक कमजोर देश नहीं बल्कि अपने हथियार खुद बनाता है और इस कार्य में यूपी बढ़-चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देता हूँ। प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार हुआ है वो अपने आप में एक मिसाल है।

परिवर्तनकारी होगा "प्रगति"- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'प्रगति' (Pro-Active Governance And Timely Implementation) प्लेटफॉर्म की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए इसे 'टीम इंडिया स्पिरिट' को मजबूत करने वाला सबसे प्रभावी माध्यम बताया है। यह रिफॉर्म आज 'पॉजिटिव गवर्नेंस' का उदाहरण बन गया है। अब फाइलों में काम अटकने के बजाय फील्ड में रिजल्ट दिख रहे हैं और केंद्र व राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से परिणाम हमारे सामने हैं। अब समस्या नहीं समाधान पर चर्चा होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए सभी अड़चनों का समाधान कर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसमें 'प्रगति' एक सशक्त आधार बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रगति केवल

बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा का मंच नहीं, बल्कि नए भारत की नई कार्यसंस्कृति का सशक्त उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रगति मॉडल की अवधारणा वर्ष 2003 में गुजरात में 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेज बाई एप्लिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) के रूप में प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्देश्य नागरिक शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। यही मॉडल आगे चलकर 'प्रगति' के राष्ट्रीय स्वरूप के रूप में विकसित हुआ, जिसने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, सामाजिक योजनाओं और सिस्टम रिफॉर्म के क्षेत्र में टीम

इंडिया अप्रोच को मजबूती प्रदान की। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति मॉडल राज्य के लिए एक गेम-चेंजर सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश आज देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4.19 लाख करोड़ की लागत के 65 बड़े प्रोजेक्ट प्रगति के अंतर्गत शामिल हैं। इनमें से 26 परियोजनाएँ पूरी होकर कमीशन हो चुकी हैं, जबकि 39 परियोजनाएँ निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में इंटर-एजेंसी बाधाओं का प्रभावी समाधान हुआ है।

मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है इसकी कला आपको अच्छी तरह मालूम है।

सीएम योगी की तारीफ में बोले राजनाथ सिंह



मैनेजमेंट मतलब "महेंद्र" ..

पूर्व कैबिनेट मंत्री, एमएलसी डॉ. महेंद्र सिंह को भाजपा का राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया जाना एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। डॉक्टर महेंद्र सिंह भाजपा के मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं।

डॉक्टर महेंद्र सिंह एक राजनेता के साथ-साथ एडवोकेट भी हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ। वर्ष 1992 में डॉक्टर महेंद्र सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1995 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वर्ष 2003 में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की है। डॉक्टर महेंद्र सिंह 2012 से उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य एमएलसी हैं। इस से पहले वे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव, असम के पूर्व प्रभारी और त्रिपुरा में भाजपा के चुनाव प्रभारी की भूमिका भी निभा चुके हैं। उनके नेतृत्व में असम में भाजपा को भारी सफलता भी हासिल हुई थी। डॉ. महेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री भी रह चुके हैं।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह को भाजपा संगठन का अनुभवी और प्रभावशाली नेता माना जाता है। संगठनात्मक कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। पार्टी नेतृत्व ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान संगठन और चुनावी मोर्चे पर उनके लगातार प्रयास और समर्पण को देखते हुए उन पर भरोसा जताया। वे कई वर्षों से संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। उनकी संगठनात्मक क्षमता और अनुभव को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय परिषद की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

डॉक्टर महेंद्र सिंह को भाजपा का एक अनुभवी और प्रखर नेता माना जाता है, जिन्हें 2014 में असम का राज्य प्रभारी नियुक्त किया गया था। उनकी रणनीतियों से पार्टी को असम में पहली बार जीत मिली। 2016 में असम में ऐतिहासिक जीत का श्रेय उन्हें दिया जाता है।



2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, उन्हें मध्य प्रदेश का राज्य प्रभारी नियुक्त किया गया, जहाँ उन्होंने सभी 29 लोकसभा सीटों में जीत दिलाने का काम किया। गौरतलब है कि पहली बार भाजपा ने मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी सीटें जीती हैं।

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भाजपा की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटों पर बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के अहम किरदार रहे प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह के जिम्मे बिहार की 58 सीटें थीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बिहार में मोर्चा संभाल लिया था। डॉ. महेंद्र सिंह पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति पर काम कर रहे थे। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने फिर अपने बूध प्रबंधन और राजनीतिक सूझबूझ से सबको चौंका दिया।

महेंद्र सिंह 2015 में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त हुए थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में इनके अथक प्रयासों से भाजपा ने प्रचंड व ऐतिहासिक जीत हासिल कर पहली बार नॉर्थ ईस्ट (असम राज्य) में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 2016 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के संयोजक रहे जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी को 2017 में अभूतपूर्व जनसमर्थन प्राप्त हुआ। डॉक्टर महेंद्र सिंह के प्रशासनिक क्षमता के कारण ही ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग में उनके उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2018 में 12 राष्ट्रीय पुरस्कारों से एवं 2019 में 24 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

बुंदेलखंड और विंध्याचल जैसे जल-संकट वाले क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से पेयजल पहुँचाने का सफल कार्य किया था। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना "हर घर जल" योजना का डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जिस तरह से नेतृत्व किया था वह आज कई लोगों के लिए एक केस स्टडी और मिशाल है। डॉ. महेंद्र सिंह के प्रशासनिक कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर कई बार सराहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े बीजेपी के नेताओं ने असम जैसे चुनौतीपूर्ण राज्यों में बीजेपी को जीत दिलवाने के लिए एक "समर्पित कार्यकर्ता" के रूप में उनकी सराहना की थी। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने चुनाव से लेकर पार्टी दायित्व को हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी बखूबी निभाया है और उनका यह सिलसिला आज भी जारी है।

तकनीक युक्त होंगे यूपी पंचायत चुनाव



उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़े-बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फर्जी वोटर्स पर लगाम लगाने के लिए इस बार बड़े फैसले लिए गए हैं। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए 2 बड़े फैसले सरकार हाल ही में लिए हैं। इनमें से एक है स्टेट वोटर नंबर और दूसरा है फेसियल रिकग्निशन सिस्टम। आयोग ने फैसला लिया है कि प्रदेश के हर पंचायत मतदाता को एक यूनिक 'स्टेट वोटर नंबर' दिया जाएगा। यह नंबर मतदाता की पहचान को पूरी तरह विशिष्ट बनाएगा और मतदाता डेटा के प्रबंधन में होने वाली गलतियों की गुंजाइश खत्म करेगा।

इसके लागू होने से एक ही व्यक्ति का नाम अलग-अलग क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज होने जैसी समस्याओं पर प्रभावी तरीके से रोक लग सकेगी। चुनाव प्रक्रिया में इस बार अब तक का सबसे बड़ा बदलाव 'फेसियल रिकग्निशन सिस्टम' के रूप में सामने आएगा। इस नई तकनीक के लागू होने से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान उनके चेहरे के जरिए की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम

पर वोट डालने की कोशिश करेगा, तो सिस्टम तुरंत उसकी पहचान कर लेगा और वह पकड़ में आ जाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले 500 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। साथ ही 75 नए ब्लॉक भी बनाए जाएंगे। इसके बाद इन नए ब्लॉकों में अलग-अलग ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा। 2021 के पंचायत चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें और 826 ब्लॉक थे। इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव के दौरान सरकार ने 107 नई नगर पंचायतें बनाई थीं, जिसके चलते 494 ग्राम पंचायतें शहरी सीमा में शामिल हो गईं। वर्तमान में प्रदेश में 57,695 ग्राम पंचायतें रह गई हैं। वहीं नए ब्लॉक बनने के बाद प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या 826 से बढ़कर 901 हो जाएगी।

नोट: पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गलियों में सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधान, बीडीसी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी झोंक दी है। पोस्टर, पर्चे और भावी उम्मीदवार वाले होर्डिंग्स लगाने शुरू हो गए हैं। स्थिति यह है कि वोटों को लुभाने के लिए कहीं कंबल बांटे जा रहे हैं, 5 साल से सुस्त पड़े नेता अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं।

सूबे में सियासी संग्राम



उत्तर प्रदेश की सियासत में अब फाइनल मैच की तैयारी चल रही है। फाइनल मैच यानी कि 2027 का विधानसभा चुनाव। लेकिन इस विधानसभा चुनाव से पहले सूबे के राजनीतिक दलों को चार सेमी फाइनल खेलना है। सेमी फाइनल यानी कि राज्यसभा, एमएलसी, पंचायत चुनाव और दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव।

ये सभी चुनाव बीजेपी, इंडिया गठबंधन और बसपा के लिए ताकत दिखाने का सबसे अहम जरिया है। इन चुनावों से इस बात का अंदाजा लगेगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन कितना पानी में होगा। ये सभी चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का एक रिहर्सल भी है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कुल 10 सीटें इस साल खाली होने वाली है। ये पूरा चुनाव अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच अलग-अलग फेज में होगा। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधायक करते हैं और यूपी में कुल 403 विधायक हैं। ऐसे में यूपी की सियासी गणित काफी अहम है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच ही मुख्य मुकाबला होगा। अगर बीजेपी इन 10 सीटों में जितनी अधिक सीटें जीतेगी, उतना ही राज्यसभा में मौजूद होगी। दरअसल, बृजलाल, डॉ० दिनेश शर्मा, गीता शाक्य, डॉ० हरदीप पुरी, रामजी गौतम, सीमा द्विवेदी, नीरज शंखर, अरुण सिंह, बीएल वर्मा, प्रोफेसर रामगोपाल यादव की राजसभा सीटें 2026 में खाली होंगी।

वहीं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 11 एमएलसी सीटों पर

भी इस साल चुनाव होंगे। ये चुनाव स्नातक और शिक्षक के वोटर द्वारा ही होते हैं। ये सीटें विधानपरिषद की कुल 100 सदस्यों में महत्वपूर्ण हैं। शिक्षक क्षेत्र में 6 और स्नातक क्षेत्र में 5 सीटें हैं। भाजपा और सपा विधानपरिषद में भी अपने आप को मजबूत करने की भरसक कोशिश करेंगे।

सबसे बड़ा सेमीफाइनल मैच उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव होने वाला है। अभी संभावना यही जताई जा रही है कि ये चुनाव अप्रैल से जुलाई के बीच हो सकता है। ग्राम पंचायत में लगभग 58,000 ग्राम प्रधान का चुनाव होगा। ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत के हजार सदस्यों के पद खाली हैं। इसके अलावा सभी जिलों में सदस्य और अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। इस तरह से कुल मिलाकर लाखों पदों पर चुनाव होंगे। इस चुनाव के जरिए ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक दलों को खड़ा होने का मौका मिलेगा।

2026 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक मऊ के घोसी विधानसभा सीट पर होगा तो दूसरा चुनाव बरेली के फरीदपुर सीट पर होगा। तीसरी सीट सोनभद्र है। यह तीनों ही सीटें मौजूदा विधायकों के निधन के बाद खाली हुई हैं। इनमें दो सीट पर सपा और एक सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है।

इन चार चुनावों से जाहिर है की साल 2026 हलचल वाला होगा, जो 2027 के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की सुगबुगाहट देगा।

माघ मेले की महिमा..

प्रयागराज में संगम की रेती पर माघ मेला चल रहा है। रोजाना 10 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद साधु-संत, अखाड़े और कल्पवासी संगम की रेती पर डेरा जमाए हुए हैं। तपस्या कर रहे हैं। मेले में साधु-संतों की मौजूदगी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी खूब वीडियो बना रहे हैं। बता दें कि इस बार 75 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इसे साधारण माघ नहीं, बल्कि 'महामाघ मेला' कहा जा रहा है, जो इसे ऐतिहासिक बना रहा है। 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले का समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ होगा।

योगी सरकार का अनुमान है कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के पर्व तक चलने वाले माघ मेले के दौरान 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम की धरती पर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेले में सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। इसी के चलते जहां माघ मेले की सुरक्षा में लगभग 10 हजार पुलिस फोर्स की तेनाती की गई है। वहीं एआई युक्त सीसीटीवी कैमरों के साथ ही ड्रोन कैमरे से पूरे मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। लेकिन माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक न हो और किसी आतंकी संगठन के नापाक मंसूबे कामयाब ना हो इसके लिए माघ मेले में यूपी एटीएस के कमांडो भी तेनात किए गए हैं।

पुराणों के अनुसार माघ मास को "देव मास" भी कहा गया है। इस दौरान संगम में किया गया स्नान, गंगा जल के समान पुण्यकारी माना जाता है। इस बार का प्रयागराज माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान कई प्रमुख स्नान पर्व और धार्मिक आयोजन होंगे। मेले की सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व बताई जा रही है। पूरे मेला क्षेत्र में 400 से अधिक एआई-इनेबलड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी भीड़ और यातायात की लगातार निगरानी की जा रही है। जल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के गोताखोरों को संगम और आसपास के घाटों पर तेनात किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए एटीएस, बम डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीएस) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की भी तेनाती की गई है। मेला क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटकर पुलिस बल की तेनाती की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

ध्यान देने वाली बात यह है कि पौराणिक ग्रंथों में प्रयागराज की बड़ी महत्ता बताई गई है। तीर्थों के राजा कहलाने वाले प्रयागराज में वेसे तो साल भर श्रद्धालु मकरवाहिनी (मां गंगा) और कूर्मवाहिनी (मां यमुना) और हंसवाहिनी (मां सरस्वती) की पवित्र त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इसका महत्व माघ के महीने में

और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रयागराज में मां गंगा और मां यमुना की लहरें तीर्थराज की चंवर की तरह प्रतीत होती हैं, उसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं। माघ मास और तीर्थों के राजा प्रयागराज की महत्ता को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि -

- माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतिहिं आव सब कोई। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहिं सकलत्रिवेनी।
- अर्थात् माघ मास के दौरान यज्ञों की इस पावन भूमि पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवतागण स्नान कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं।



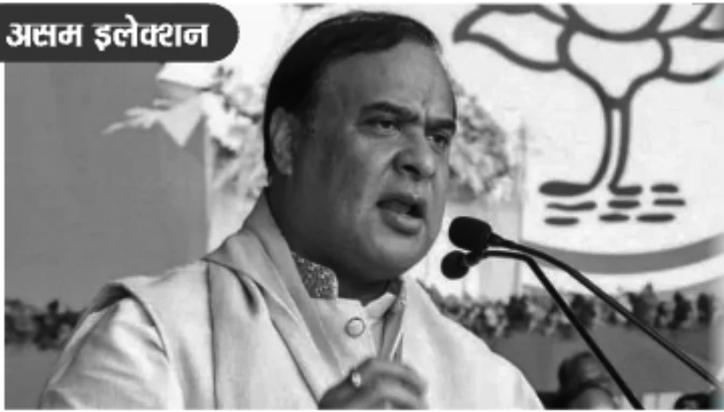
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी को माघ मेला-2026 के दौरे के दौरान प्रयागराज में गंगा नदी में पूजा-अर्चना और अनुष्ठान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ माघ मेले में आने वाले 'स्नान पर्व' की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने गंगा पूजन सहित कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि माघ मेले के दौरान छह मुख्य स्नान होंगे, जो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ खत्म होंगे। इस साल की महत्वपूर्ण स्नान की तारीखों में 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मोनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि शामिल हैं। माघ मेला-2026 की भव्य शुरुआत ने एक बार फिर प्रयागराज को आस्था और संस्कृति के एक शाश्वत केंद्र के रूप में उसकी स्थिति की पुष्टि की है।

परिवर्तनकारी होगा "प्रगति".. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'प्रगति' (Pro-Active Governance And Timely Implementation) प्लेटफॉर्म की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए इसे 'टीम इंडिया स्पिरिट' को मजबूत करने वाला सबसे प्रभावी माध्यम बताया है। यह रिफॉर्म आज 'पॉजिटिव गवर्नेंस' का उदाहरण बन गया है। अब फाइलों में काम अटकने के बजाय फील्ड में रिजल्ट दिख रहे हैं और केंद्र व राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से परिणाम हमारे सामने हैं। अब समस्या नहीं समाधान पर चर्चा होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए सभी अड़चनों का समाधान कर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसमें 'प्रगति' एक

सशक्त आधार बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रगति केवल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा का मंच नहीं, बल्कि नए भारत की नई कार्यसंस्कृति का सशक्त उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रगति मॉडल की अवधारणा वर्ष 2003 में गुजरात में 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेज बाई एप्लिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) के रूप में प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्देश्य नागरिक शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और जवाब देही सुनिश्चित करना था। मॉडल आगे चलकर 'प्रगति' के राष्ट्रीय स्वरूप के रूप में विकसित हुआ, जिसने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, सामाजिक योजनाओं और सिस्टम रिफॉर्म के क्षेत्र में टीम इंडिया अप्रोच को मजबूती प्रदान की। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति मॉडल राज्य के लिए एक गेम-चेंजर सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश आज देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4.19 लाख करोड़ की लागत के 65 बड़े प्रोजेक्ट प्रगति के अंतर्गत शामिल हैं। इनमें से 26 परियोजनाएँ पूरी होकर कमीशन हो चुकी हैं, जबकि 39 परियोजनाएँ निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में इंटर-एजेंसी बाधाओं का प्रभावी समाधान हुआ है। राजस्व, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन, नगर विकास, पंचायती राज सहित सभी संबंधित विभाग एक ही मंच पर बैठकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति जैसे तकनीक-आधारित प्लेटफॉर्म के कारण उत्तर प्रदेश आज बॉटलनेक स्टेट से ब्रेकथू स्टेट में परिवर्तित हो चुका है। राज्य सरकार अब केवल फेसिलिटेटर नहीं, बल्कि एक्सेलेरेटर की भूमिका में परियोजनाओं को गति दे रही है।

(Party-wise seats and vote share)

PARTY	SEATS (126)	VOTE SHARE
BJP	60	33.2%
AJP	9	8%
INC	29	29.67%
AIUDF	16	9.29%
OTHERS	12	19.84%



असम के विधानसभा चुनाव के लिए अभी 3-4 महीने का समय बाकी है। लेकिन सत्तारूढ़ BJP चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी असम में लगातार जीत का हैट्रिक लगाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। असम 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति के केंद्र में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा बीजेपी के लिए न केवल राज्य के चेहरे हैं, बल्कि 2026 विधानसभा चुनावों की रणनीति के प्रमुख सूत्रधार भी हैं। पूर्व कांग्रेस नेता से बीजेपी में आने के बाद उन्होंने असम को 'हिंदुत्व + विकास' मॉडल पर चलाया, जो अब तीसरी बार लगातार जीत का आधार बनेगा। सरमा का नेतृत्व एनडीए को 100+ सीटों का लक्ष्य दिलाने का दावा कर रहा है, लेकिन उनकी भूमिका भ्रुवीकरण, संगठन मजबूती और विपक्ष पर हमले पर केंद्रित है। सरमा उपलब्धियों जैसे ओरुणोदोई से 27 लाख महिलाओं को सहायता, 18 मेडिकल कॉलेज, बाढ़ नियंत्रण, सेमीकंडक्टर प्लांट को हाईलाइट कर रहे हैं। नवंबर 2025 में सीएम सरमा ने कहा, "मियां एकजुट वोट करते हैं, हमारे वोट बिखरे हैं, एकजुट होकर दबाव बनाओ।" अभी BJP-NDA के पास 84 सीटें हैं और पार्टी अब 100+ सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूती, युवा-महिला उम्मीदवारों पर फोकस, और जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने की रणनीति तैयार की है।

डिलिमिटेशन के बाद असम की 126 सीटों में से जनसांख्यिकीय पैटर्न हिंदू-असमिया बहुल क्षेत्र के आधार पर बीजेपी और सहयोगी एजीपी, यूपीपीएल, बीपीएफ 103 सीटों पर मजबूत हैं। बाकी 23 मुस्लिम-बहुल सीटों पहले 30 थीं, अब घटी हैं लेकिन बीजेपी और एनडीए के लिए चुनौती है, बीजेपी 6 ऐसी सीटों को टारगेट कर रही है जिसपर वो कमजोर है। एंटी-इनकंबेन्सी से बचने के लिए कई मौजूदा विधायकों यहां तक कि एक मंत्री का टिकट कट सकता है। युवा और महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी, खासकर नई बनी 10-15 सीटों पर। एजीपी, बीपीएफ, यूपीपीएल के साथ नई रणनीति बनाई जा रही है।

जैसे बोडोलैंड में बीपीएफ को फिर शामिल किया गया है।

सरमा का सफर: हिमंत बिस्वा सरमा का जन्म 1 फरवरी 1969 को गुवाहाटी में हुआ। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद हिमंत ने 5 साल तक गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत की।

हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1991 में कांग्रेस से की थी। वे पहली बार 2001 में जालुकबारी सीट से कांग्रेस टिकट पर विधायक बने। इसके बाद उन्होंने लगातार 2006 और 2011 में भी जीत दर्ज की। 2011 का चुनाव कांग्रेस से उनका आखिरी विधानसभा चुनाव था। उन्होंने 2015 में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। 23 अगस्त 2015 को हिमंत बिस्वा सरमा भाजपा में शामिल हुए। उनकी एंटी ने न सिर्फ असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति का समीकरण बदल दिया। साल 2021 विधानसभा चुनाव में भाजपा की वापसी के बाद सरमा को विधायक दल का नेता चुना गया और वे असम के मुख्यमंत्री बने। आज वे भाजपा के लिए पूर्वोत्तर की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा हैं। 2016 में असम विधानसभा चुनाव जीतने के ठीक बाद हिमंत को बीजेपी ने नॉर्थ-ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (NEDA) का अध्यक्ष बनाया था।

हिमंत बिस्वा सरमा का सफर बताता है कि कैसे 2011 तक कांग्रेस के मजबूत चेहरे रहे नेता आज भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार और मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आज वो पूर्वोत्तर में भाजपा का असली मास्टरमाइंड है।

हर ओर “हिमंत”

पारदर्शी होती परीक्षाएं

उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का द्वार हैं। 2017 के पहले इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया है। सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। आज उत्तर प्रदेश में बिना किसी सिफारिश या खर्ची-पर्ची के योग्य अभ्यर्थी नौकरी पा रहे हैं। यह बदलाव न केवल युवाओं के सपनों को साकार कर रहा है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बना रहा है।

2012 से 2017 तक की अवधि उत्तर प्रदेश में भर्ती घोटालों और पेपर लीक की काली घाटों से भरी रही। इस दौरान कई प्रमुख परीक्षाओं में अनियमितताएं सामने आईं, जैसे 2014 में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्री-मेडिकल टेस्ट (UP-CPMT) का पेपर लीक होना, जहां प्रश्नपत्रों की सीलबंद बॉक्सेस से छेड़छाड़ पाई गई, जिसके कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी और लाखों छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में डाल दिया गया। इसी तरह 2015 में प्रांतीय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (UPPCS) का पेपर क्लाउडसप पर लीक हो गया, जिसके कारण अखिलेश यादव सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी और छात्रों ने लखनऊ, इलाहाबाद व कानपुर में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती, शिक्षक भर्ती और अन्य चयनों में भी व्यापक धांधली,

मेरिट में हेरफेर और पक्षपात के आरोप लगे, जिससे अदालती हस्तक्षेप हुए और भर्तियां वर्षों लटकी रहीं। इन घटनाओं ने युवाओं का विश्वास तोड़ा और राज्य में बेरोजगारी भत्ते जैसी योजनाओं में भी फर्जीवाड़ा सामने आया।

योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही प्रतियोगी परीक्षाओं में व्याप्त अनियमितताओं पर कड़ा प्रहार किया। पहले की सरकारों में पेपर लीक, नकल और सॉल्वर गैंग जैसी समस्याएं आम थीं, जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती थीं। लेकिन 2017 के बाद सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। पेपर लीक करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने के निर्देश दिए गए। एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की व्यवस्था की गई। परिणामस्वरूप, भर्ती प्रक्रियाएं भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से मुक्त हुईं।

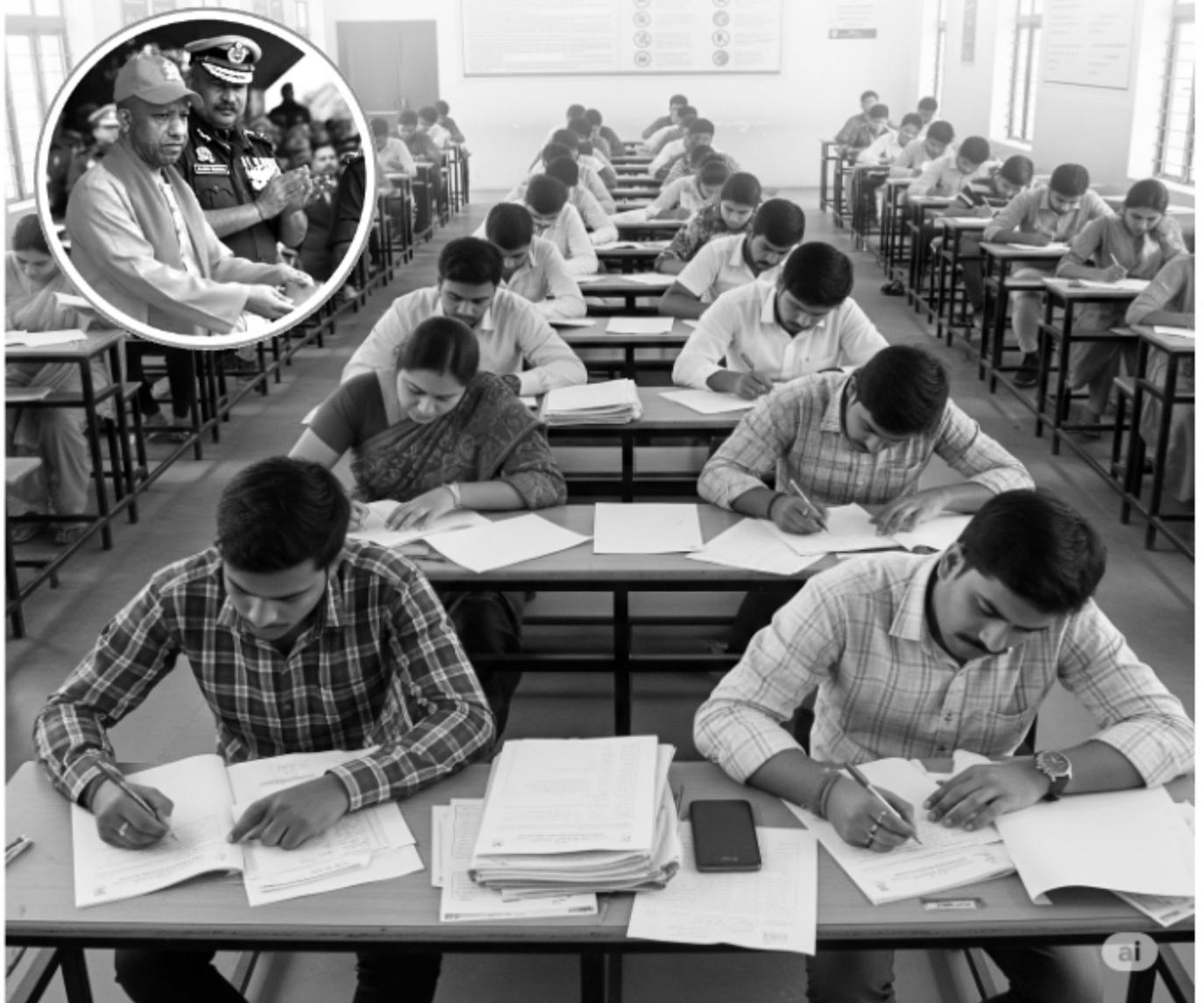
हाल ही में योगी सरकार ने पुलिस भर्ती में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 32,679 पदों की भर्ती के लिए सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को एक बारगी तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है। इससे उन लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा, जो पिछले वर्षों में देरी के कारण आयु सीमा पार कर चुके थे। यह निर्णय न केवल अभ्यर्थियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी इस

आदेश से पुलिस बल में योग्य और उत्साही युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे कानून-व्यवस्था और मजबूत होगी।

सरकार ने तकनीकी सुधारों पर भी जोर दिया। डिजिटल मॉनिटरिंग, सीसीटीवी निगरानी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को मजबूत बनाया गया। 2024 में उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अध्यादेश लाया गया, जिसमें पेपर लीक करने वालों को आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इससे न केवल अपराधियों में डर पैदा हुआ, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता बनी रही। पिछले आठ वर्षों में 8.50 लाख से अधिक सरकारी नोकरियां पारदर्शी तरीके से दी गईं, जिसमें पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभाग शामिल हैं। यह आंकड़ा खुद बताता है कि सरकार युवाओं के हित में कितनी प्रतिबद्ध है। योगी सरकार की इन पहलों से स्पष्ट है कि प्रतियोगी परीक्षाएं अब केवल योग्यता की

परीक्षा हैं। पहले जहां भर्तियां वर्षों लटकती रहीं थीं, वहीं अब समयबद्ध और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जा रही है। योगी सरकार ने न केवल पेपर लीक पर अंकुश लगाया, बल्कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, जैसे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसमें मुफ्त कोचिंग और मार्गदर्शन दिया जाता है।

योगी सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को एक नया आयाम दिया है। पारदर्शिता, मेरिट और युवा हित को सर्वोपरि रखते हुए उठाए गए कदम उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों के लिए मॉडल बना रहे हैं। इन प्रयासों से युवा वर्ग में विश्वास जागा है कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सरकार की यह प्रतिबद्धता राज्य के विकास और युवा सशक्तिकरण की मजबूत नींव है। आने वाले समय में और अधिक सुधारों की उम्मीद है, जो उत्तर प्रदेश को समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाएं।



सा ल साल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है. संगठन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ने आगामी 100 दिनों की कार्ययोजना तैयार की है। राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा पार्टी की प्रमुख नेता और उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रिय राजनीति के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हमेशा ही महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक संघर्ष के प्रतीक के रूप में खुद को स्थापित किया है। उनका मशहूर नारा 'लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ' उनके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का परिचायक है। यह नारा 2022 के यूपी चुनाव में ट्रेडिंग में भी था। अब 2027 की राजनीतिक लड़ाई में उनकी वापसी की संभावनाएं चर्चा में हैं। प्रियंका गांधी की यूपी कांग्रेस में वापसी की चर्चा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है। इस बात की चर्चा उस समय शुरू हुई जब यूपी कांग्रेस की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया। कांग्रेस के इस बयान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने जा रही हैं। कांग्रेस ने 12 जनवरी 2026 को प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में एक साथ पत्रकार वार्ता करने का फैसला लिया।

प्रियंका की प्लानिंग..



प्रियंका गांधी के बारे में जानिए...



जन्म:
12 जनवरी 1972
(दिल्ली)

शिक्षा: स्नातकोत्तर

पार्टी



भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस



मां
सोनिया गांधी



पिता
राजीव गांधी



पति
रॉबर्ट वाड़ा

कांग्रेस के यूपी के नेताओं और कैडर का मानना है कि यदि प्रियंका फिर से प्रदेश चुनाव का जिम्मेदारी संभालती हैं तो यह तय है सपा के साथ सीट शेयरिंग में ज्यादा तकरार नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान जब कुछ सीटों पर पेच फंसा तो कांग्रेस की ओर से प्रियंका ने ही कमान संभाली थी। लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ सीटों पर कांग्रेस और सपा के बीच बात फंसी थी, जिसकी वजह से गठबंधन के स्वरूप पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका था। जिसके बाद प्रियंका ने खुद इस मामले में पहल की और राहुल से बातचीत के बाद अखिलेश यादव चर्चा की ओर सीट बंटवारे पर बात बन गई थी। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का कहना है कि अगर यह चुनाव INDIA गठबंधन के तहत लड़ा जाता है, तो जैसा निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा, उसी रणनीति पर पार्टी आगे बढ़ेगी।

संगठन की सर्जरी: अभियान के तहत पूरे देश में एक साल तक संगठन को खड़ा करने का काम किया। यूपी में इस अभियान के दौरान एक साल में जिला और शहर अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, इसके बाद कमेटियां बनाई गईं। ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष बनाए गए और 20-25 ब्लॉकों को मिलाकर मंडल गठित किए गए। हर बूथ पर अध्यक्ष नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसका करीब 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

इंदौर पर कलंक..

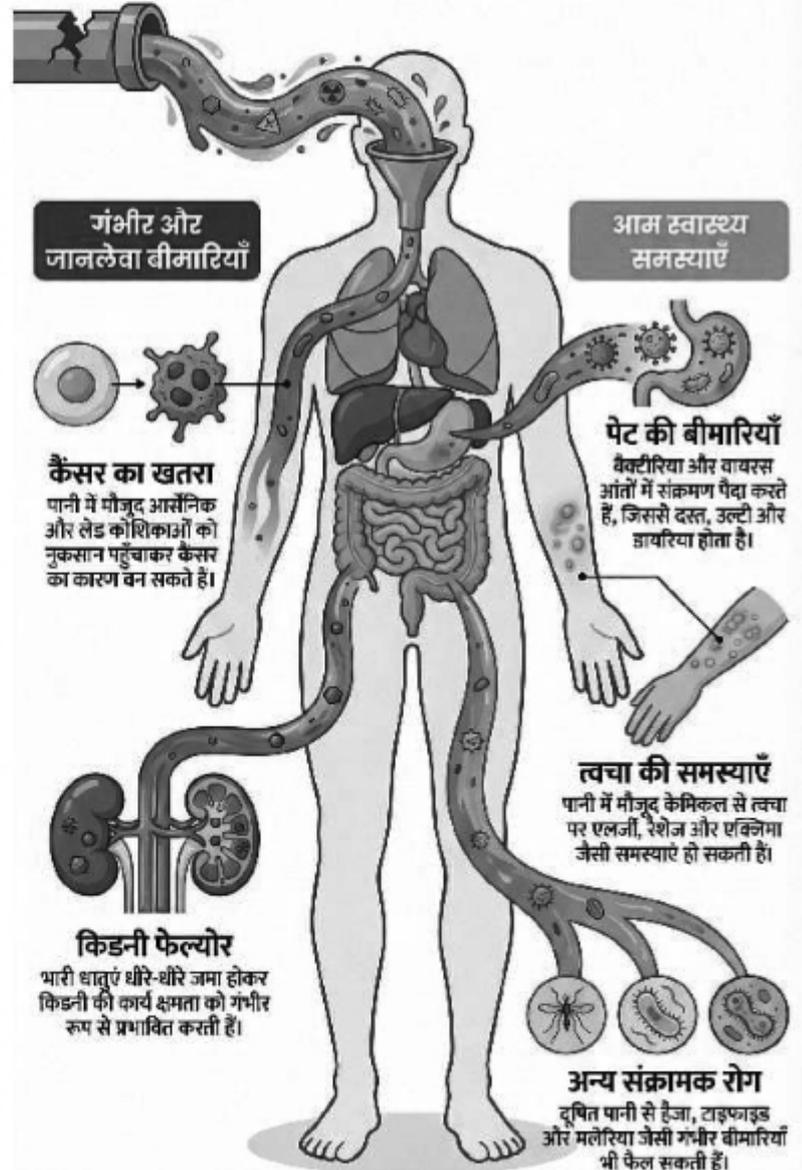
देश का "सबसे साफ शहर" कहलाने वाला इंदौर आज एक भयावह सच्चाई से रू-बरू है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 1400 से अधिक लोग बीमार पड़ चुके हैं। जो शुरुआत में एक "दुर्भाग्यपूर्ण हादसा"

बताया जा रहा था, वह अब ठेके की देरी, प्रशासनिक लापरवाही और निगरानी की विफलता का घातक उदाहरण बन चुका है। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतें यह हादसा नहीं था, यह लापरवाही थी। यह त्रासदी टाली जा सकती थी। लेकिन नगर निगम और जल विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। भागीरथपुरा की पुरानी पाइपलाइन बदलने के लिए अगस्त 2025 में ही 2.40 करोड़ का टेंडर जारी किया गया था, जिसमें गंदे और बदबूदार पानी की शिकायतों का जिक्र था। लेकिन न टेंडर खोला गया, न काम शुरू हुआ, न आपात मरम्मत की गई। लोगों की मौत के बाद जाकर टेंडर आनन-फानन में खोला गया। पंचायत ग्राउंड जीरो की "जन सरोकार टीम" की जांच में यह नाकामी और लापरवाही पता चली। हमारी इस जन सरोकार टीम के सदस्यों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में लोगों ने बताया कि कई बार बदबूदार पानी की शिकायत स्थानीय पार्षद और नगर निगम के दफ्तर में की गई थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, नतीजा आज सामने है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को दो हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। सरकार ने भी मामले में तीन सदस्यीय जांच समिति बना दी गई है। जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव को सौंपी गई है। कुछ निचले स्तर के अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा हैं, टेंडर समय पर क्यों नहीं खोला गया? लीकेज समय रहते क्यों नहीं ठीक किया गया? लोगों की शिकायतों को क्यों अनसुना किया गया? और सिस्टम तब क्यों जागा जब लाशें आने लगीं? इंदौर अपनी सफाई पर गर्व करता है। लेकिन भागीरथपुरा में सफाई के तमगे

तब खोखले साबित हो गए जब नलों से पानी नहीं, जहर बहा और प्रशासन चुप रहा। यह हादसा नहीं था। यह एक सिस्टम की विफलता थी। और इसकी कीमत दो दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई।

दूषित पानी: स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा



लालू यादव की पार्टी और परिवार के भीतर मची सियासी रार थमी नहीं है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने 9 जनवरी को सोशल मीडिया पर 'अपनों' और 'नए करीबियों' को षड्यंत्रकारी बताते हुए तीखा हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि किसी बड़ी विरासत को नष्ट करने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने ही लोग और कुछ षड्यंत्रकारी काफी होते हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि जिस विरासत को बड़ी मेहनत और शिद्दत से खड़ा किया गया, उसे नुकसान पहुंचाने में अक्सर अपने ही लोग आगे आ जाते हैं। रोहिणी ने पोस्ट में आगे लिखा, "जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है। तब 'विनाशक' ही आंख-नाक और कान बन बुद्धि-विवेक हर लेता है।" इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद भी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार त्यागने और राजनीति छोड़ने की घोषणा की थी। रोहिणी ने खुद को अपमानित बताते हुए बताया कि उनके ऊपर चप्पल तक फेंककर मारी गई। वहीं लालू यादव परिवार को

एक और बड़ा झटका 9 जनवरी को कोर्ट की तरफ से मिला।

जमीन के बदले नौकरी से जुड़े कथित घोटाले के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। यादव परिवार ने रेल अधिकारियों और अपने करीबी सहयोगियों की मिलीभगत से जमीनें हासिल की। अदालत ने इस मामले में 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए और 52 लोगों को बरी कर दिया, जिनमें रेल अधिकारी भी शामिल थे। सीबीआई की चार्जशीट में नामित 103 आरोपियों में से पांच की मृत्यु हो चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी

लैंड लालची "लालू"

यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे। उस दौरान भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र (जबलपुर) में ग्रुप-डी पदों पर नियुक्तियां नियमों को दरकिनार कर की गईं। सीबीआई के अनुसार, ये नौकरियां उन लोगों को दी गईं जिन्होंने लालू यादव के परिवार या उनके करीबी लोगों के नाम पर जमीन उपहार में दी या ट्रांसफर की। एजेंसी का दावा है कि इन सौदों में बेनामी संपत्तियां भी शामिल थीं, जो आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती हैं।

लैंड फॉर जॉब स्कैम

लालू परिवार पर कसेगा शिकंजा !



नौकरी के बदले जमीन घोटाला

क्या है नौकरी के बदले जमीन घोटाला?



- 2004 से 2009 के बीच जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने का आरोप
- जबलपुर में भारतीय रेलवे की ग्रुप-डी की नौकरियों में घोटाले का आरोप
- इस दौरान राजद प्रमुख लालू यादव यूपीए सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री थे

नौकरी के बदले जमीन घोटाला

लालू परिवार को बड़ा झटका

- लालू परिवार के छह सदस्यों समेत 41 लोगों पर तय हुए आरोप
- आरोपियों में लालू के साथ पत्नी राबड़ी, बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप भी
- लालू यादव की दो बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव भी आरोपियों में
- कुछ रेलवे अधिकारियों सहित 52 लोग बरी, पांच आरोपियों की मौत



अखिलेश की स्ट्रेटजी



समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में मिले बेहतरीन परिणाम को बरकार रखना चाहती है। इसीलिए पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में तय किया गया है कि विधानसभा सीटवार सर्वे कराते हुए पता लगाया जाएगा कि जनाधार वाला कौन नेता है। इसीलिए अभी से दावेदारों के नाम लिए जा रहे हैं। सर्वे में देखा जाएगा कि दावेदारों की संबंधित सीट पर कितनी पकड़ है। जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारी फिट बैठ रही है या नहीं। सभी कसौटी पर खरा उतरने वालों का टिकट फाइनल किया जाएगा। जमीनी पकड़ न होने पर टिकट नहीं दिया जाएगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में इन दिनों लगातार प्रदेशभर से आने वाले कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और दावेदारों के बारे में फीड बैक भी प्राप्त कर रहे हैं। सपा चुनाव में ब्राह्मण उम्मीदवारों पर भी खासा दांव लगाने पर मंथन चल रहा है। सपा अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के साथ अन्य दल से आने वाले मजबूत दावेदारों के नामों पर भी विचार करने की योजना पर काम कर रही है। सपा का मानना है कि ब्राह्मणों की नाराजगी का फायदा उसे मिल सकता है। प्रदेश में ब्राह्मण बाहुल्य सीटों पर उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, जिनकी अपनी सीट पर मजबूत पकड़ होगी। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सपा ने अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए एक बार फिर से बड़े स्तर पर पार्टी में ओवरहालिंग करने की तैयारी में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने पर जोर दे रहे हैं। सभी

वर्गों और जातियों के नेताओं को संगठन में प्रतिनिधित्व देने की योजना बनाई जा रही है, ताकि पार्टी का जनाधार मजबूत हो सके। किसी भी एक जिले में टिकट देने में वहां की सभी प्रमुख जातियों को एडजस्ट किया जाना संभव नहीं है, इसके लिए सपा ने खास रणनीति तैयार की है। इसके तहत कुछ जातियों को टिकट दिया तो कुछ को संगठन में अहम स्थान दिया जाएगा। सपा के लिए एक गुड न्यूज यह भी है कि उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें से एक मऊ की घोसी विधानसभा सीट भी है। अब कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रमुख अजय राय ने खुद ऐलान किया है कि कांग्रेस घोसी में समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन करेगी।

सपा की स्थिति (2022 के विधानसभा चुनाव)

लड़ी-347, जीती-111 | मत मिले-29543934 | मत प्रतिशत-32.02

सपा का लोकसभा इतिहास

चुनाव	वोट %	सीटें
1996	20.84	16
1998	73	19
1999	24.04	26
2004	26	35
2009	23.26	26
2014	22.20	5
2019	18.11	5
2024	33.59	37





राम मंदिर से रिकॉर्डतोड़ कमाई!

आस्था ने बदली अयोध्या की अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था बढ़ाता अध्यात्म..

भारत उत्सवों का देश है और यहां इतने पर्व-त्योहार मनाये जाते हैं कि एक के खत्म होते ही दूसरे की प्रतीक्षा शुरू हो जाती है। उत्तर और पूर्वी भारत में जहां दिवाली, होली और दशहरा जैसे त्योहार धूमधाम से मनाये जाते हैं, वहीं दक्षिण और पश्चिम भारत में ओणम, पोंगल, गणेश चतुर्थी जैसे पर्वों की धूमधाम देखते ही बनती है। इन त्योहारों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं और काफी खर्च करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से दिवाली में बिक्री काफी बढ़ी है। हमारे पर्व-त्योहारों में इतना कुछ खरीदा जाता है कि हाथ से बनने वाली चीजों से लेकर कारखानों में उत्पादित होने वाले सामान की बिक्री बढ़ जाती है। छोटे और मझोले उद्योगों को ये बहुत सहारा देते हैं। अक्षय तृतीया तो खरीदारी का त्योहार है, जिसमें गहनों के अलावा वाहन वगैरह भी खरीदे जाते हैं। कपड़े तो अमूमन हर बड़े पर्व-त्योहार में खरीदे जाते हैं। वस्त्र तैयार करने में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर ऐसे ही नहीं है। इसका एक कारण हमारे पर्व-त्योहार और धार्मिक अवसर या अनुष्ठान भी हैं। हमारे यहां शादियों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो अब काफी बड़े पैमाने पर होने लगी है और इनमें बहुत खर्च होने लगा है। पैसेवाले लोग तो कई-कई आयोजन करते हैं, जिनमें करोड़ों-अरबों रुपये खर्च होते हैं। इनसे भी अर्थव्यवस्था में तेजी आती है और कारीगरों को काम मिलता है।

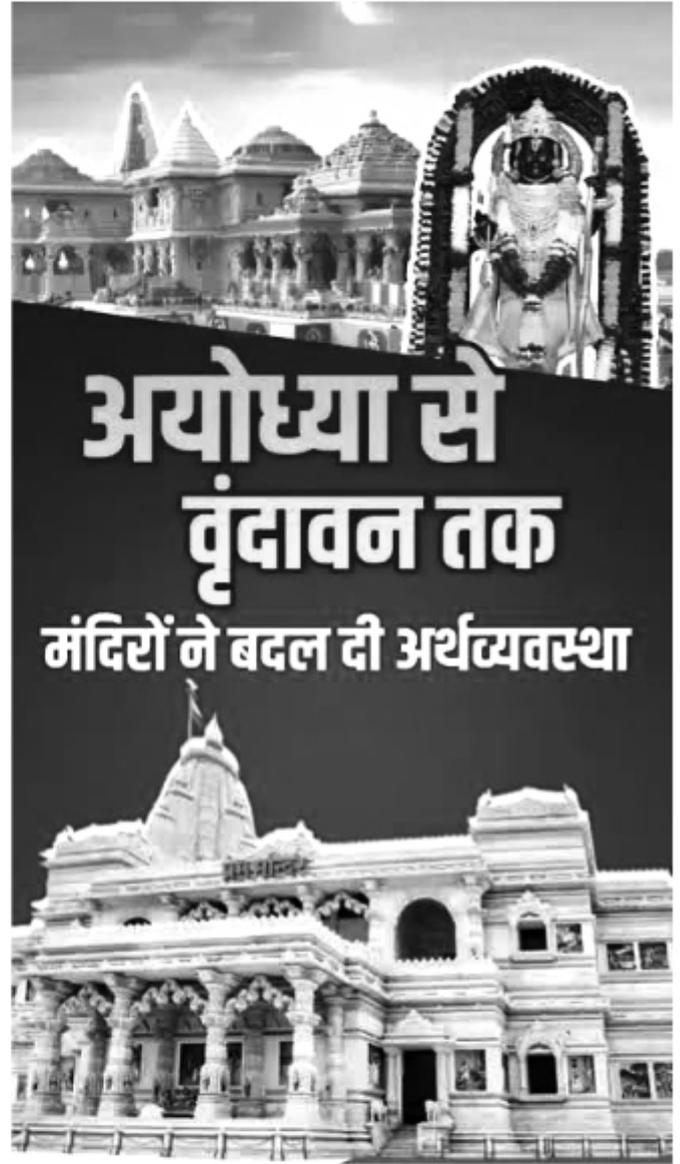
कई दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर हलवाई, सजावट का काम करने वाले, फूल बेचने वाले, दर्जी तथा उपहार सामग्री वगैरह का काम करने वालों की चांदी हो जाती है, जिनसे कई बार तो साल भर की कमाई हो जाती है। उत्सवों में दान देने की बड़ी परंपरा रही है और लोग अब दान भी काफी देते हैं। इससे उन बेसहारा लोगों को भी काफी कुछ मिल जाता है, जो लाचार हैं। कुल मिलाकर हमारा धार्मिक पर्यटन और उत्सव देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। लोग धर्म-संस्कृति के गौरव और इसमें जुड़ते जा रहे नए-नए अध्यायों को जी भरकर जीना चाह रहे हैं। देश में हाल के बरस में धर्म और अध्यात्म के नजरिए से काफी-कुछ बदला है।

लंबे अरसे बाद अयोध्या में अद्भुत राम-मंदिर का बनना, फिर भव्य समारोह में मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा ने सबको चकित कर दिया। घंटे-घड़ियाल की गूंज और शंखनाद के बीच कई-कई घंटों तक इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ। इसके बाद अथाह भीड़ उमड़ने लगी। दरअसल, नया राम मंदिर बनना अयोध्या ही नहीं, बल्कि इस देश की बड़ी ऐतिहासिक घटना है, जिसके सभी गवाह बनने को आतुर हैं।

महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़े अनेक प्रसंगों को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है। लोगों के बीच इसका आकर्षण

अयोध्या, उज्जैन तो सिर्फ उदाहरण हैं। इस कड़ी में अब तक अनेक जगहों के नाम या तो जुड़ चुके हैं या निकट भविष्य में जुड़ने वाले हैं। धार्मिक पर्यटन में उछाल के पीछे सरकार की योजनाओं का भी बड़ा रोल है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के सर्किट बनाए गए हैं, जिन पर काम चल रहा है। सर्किट में सभी धर्मों से जुड़े स्थलों को जगह दी गई है, क्योंकि इस सेगमेंट में विदेशी सेलानियों की भी अच्छी-खासी भागीदारी है। जेफरीज नामक एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज कम्पनी ने बताया है कि अयोध्या में निर्मित प्रभु श्रीराम के मंदिर से भारत की आर्थिक सम्पन्नता बढ़ने जा रही है। दिनांक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में सम्पन्न हुए प्रभु श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद स्थानीय कारोबारी अपना उज्ज्वल भविष्य देख रहे हैं। अयोध्या धार्मिक पर्यटन का हब बनाने जा रहा है तथा अब अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जेफरीज के अनुसार अयोध्या में प्रति वर्ष 5 करोड़ से अधिक पर्यटक आ सकते हैं। अभी अयोध्या में केवल 17 बड़े होटल हैं इनमें कुल मिलाकर 590 कमरे उपलब्ध हैं। लेकिन, अब 73 नए होटलों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 40 होटलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ भी हो चुका है। अभी तक नए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, टाउनशिप और रोड कनेक्टिविटी में सुधार जैसे कामों पर 85,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस निवेश का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर दिखाई देने जा रहा है। शीघ्र ही अयोध्या वैश्विक स्तर पर धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। इससे होटल, एयरलाइन, हॉस्पिटलिटी, ट्रेवल, सिमेंट जैसे क्षेत्रों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। भारत के विभिन्न शहरों से 1000 के आसपास नई रेल अयोध्या के लिए चलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे देश से दिनांक 23 जनवरी 2024 के बाद से प्रतिदिन भारी संख्या में धार्मिक पर्यटक अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि पहिले दिन ही 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रभु श्रीराम के दर्शन किये हैं। अभी अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अयोध्या में रुकते नहीं थे प्रातः अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्रीराम के दर्शन कर शाम तक वापिस चले जाते थे परंतु अब अयोध्या को इतना आकर्षक रूप से विकसित किया गया है कि श्रद्धालु 3 से 4 दिन रुकने का प्रयास करेंगे। एक अनुमान के अनुसार, प्रत्येक पर्यटक लगभग 6 लोगों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है। इस संख्या के हिसाब से तो लाखों नए रोजगार के अवसर अयोध्या में उत्पन्न होने जा रहे हैं। अयोध्या के

आसपास विकास का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब अयोध्या के रूप में वेटिकन एवं मक्का का जवाब भारत में खड़ा होने जा रहा है।

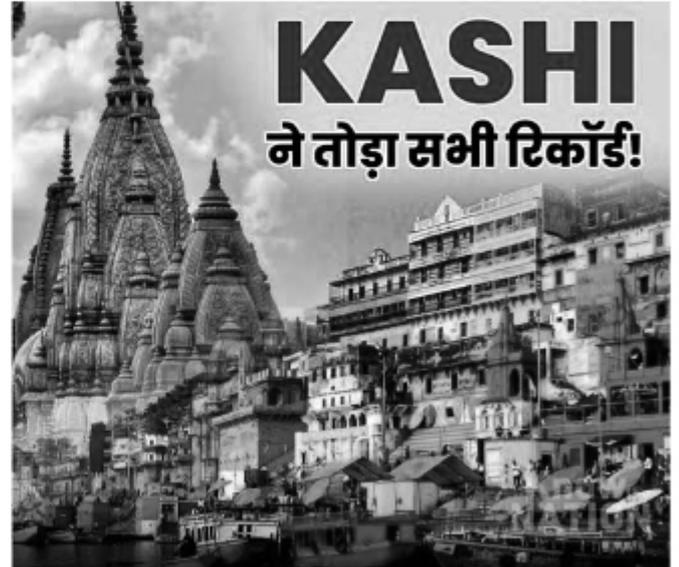


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2029 तक उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने को लेकर एक व्यापक कार्ययोजना पर काम कर रहे हैं। अयोध्या का पर्यटन सीएम योगी के इस मिशन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में अभी 1.5% योगदान कर रहा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से अयोध्या की हिस्सेदारी और बढ़ जाएगी। अयोध्या में 2024 में रिकॉर्ड 16 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे जो न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक आंकड़ा है।

यह अरब के मक्का के 1 करोड़ और इटली के वेटिकन सिटी के 90 लाख से कहीं अधिक संख्या है। अयोध्या को राम मंदिर निर्माण के बाद से जबरदस्त आर्थिक फायदा हुआ है। 2023-24 का आंकड़ा देखें तो अयोध्या का जीएसटी कलेक्शन 1798.22 करोड़ रुपये रहा। 2021-22 में यही आंकड़ा मात्र 990.14 करोड़ था। इस समय अयोध्या अपने 69,656 व्यापारियों के दम पर आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर है। अयोध्या में जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, कहा जा रहा है कि 75000 करोड़ की योजनाओं पर काम हो रहा है, 18 लाख करोड़ की योजना है। एयरपोर्ट बन गया है, नई ट्रेनें शुरू हो रही हैं। तो कहीं न कहीं धार जो है विकास की, उसको गति मिल रही है। 22 जनवरी 2024 में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद 6 महीने में यहां करीब 11 करोड़ पर्यटक आए। केवल जनवरी में ही यहां करीब 7 करोड़ की संख्या में रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे। यह किसी जगह एक महीने में आने वाले पर्यटकों का रिकॉर्ड है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यही स्थिति वाराणसी की भी है। यहां 6 महीनों के दौरान 4.59 करोड़ पर्यटक पहुंचे। साल गुजरते-गुजरते यह संख्या और बढ़ती ही जा रही है। घरेलू पर्यटकों के जरिए धार्मिक स्थलों के प्रति बढ़ते रुझान के मद्देनजर योगी सरकार केंद्र की मदद से ऐसे कई स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को केंद्र में रखते हुए कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसमें प्रमुख हैं, विंध्य धाम कॉरिडोर मिर्जापुर, नाथ कॉरिडोर बरेली। ब्रज क्षेत्र विकास परिषद, रामायण, बौद्ध, कृष्ण सर्किट, स्वदेश दर्शन आदि योजनाओं से उत्तर प्रदेश के पर्यटन को और विस्तार मिल रहा है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ईको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन पर भी लगातार फोकस कर रही है। 2025 का साल भारतीय पर्यटन के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, खासकर धार्मिक पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश का सबसे ज्यादा विजिटेड स्टेट बना, बल्कि इसकी धार्मिक जगहों ने लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश 2025 में सबसे ज्यादा विजिटेड स्टेट रहा। घरेलू पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। प्रयागराज और छोटे शहरों में स्टे सर्च 3-4 गुना बढ़ी। स्पिरिचुअल और नेचर ट्रेवल में भी 20 फीसदी की ग्रोथ के साथ वाराणसी जुड़ा रहा, लेकिन यूपी का धार्मिक आकर्षण बेजोड़ साबित हुआ। ट्रेवल एजेंट की मानें तो 2025 में Gen-Z युवा भी स्पिरिचुअल ट्रिप्स पर ज्यादा आए, जो पहले पार्टी डेस्टिनेशंस चुनते थे। इस बूम के पीछे योगी सरकार की मेहनत है।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेहतर कनेक्टिविटी और प्रमोशन ने

बड़ी भूमिका निभाई। 2025 ने साबित कर दिया कि धार्मिक पर्यटन अब सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ड्राइवर भी है। उत्तर प्रदेश ने राम मंदिर, काशी, मथुरा और संगम जैसे आकर्षणों से दुनिया को दिखाया कि भारत की स्पिरिचुअल हेरिटेज कितनी जीवंत है। जो लोग साल 2026 में स्पिरिचुअल जर्नी प्लान कर रहे हैं, वे उत्तर प्रदेश टॉप को टॉप रख रहे हैं।



KASHI

ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड!

काशी ने 2025 में करीब **14.7 करोड़** पर्यटकों का स्वागत कर वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नया कीर्तिमान स्थापित किया।

**पर्यटन ग्राफ नहीं,
ये काशी का गौरव है!**

वाराणसी में 2024 के दौरान पर्यटन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. वर्ष 2023 के मुकाबले 2024 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 34.85% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कुल 2 करोड़ 6 लाख से ज्यादा भारतीय और विदेशी सैलानी काशी पहुंचे.



मिशन "27" पर मायावती



अपने जन्मदिन (15 जनवरी) पर मीडिया से बात करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडों और माफियाओं का राज था, जिसमें दलित सबसे अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि 'जब BSP ने 2 जून 1995 को लखनऊ गेस्ट हाउस में SP से गठबंधन तोड़ा, तब हजारों SP गुंडों ने मुझे मारने की नीयत से हमला किया। उनकी सरकार केवल अपनी जाति के लोगों को लाभ पहुंचाती थी, मुस्लिम समुदाय भी प्रभावित हुआ। यही उनके कथित PDA का सच है।'

मायावती ने उत्तर प्रदेश के लोगों को चेताया कि विंटर सेशन के दौरान केवल बीजेपी ही नहीं, बल्कि SP और कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं ने भी अपनी उपेक्षा पर चिंता जताई। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार में सभी समुदायों को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व मिला था। मायावती ने कहा कि बसपा ने हमेशा ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि 'मैं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी मेहनत करूंगी। पार्टी के केडर को किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए।'

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का नाम दशकों तक शक्ति, अनुशासन और दलित राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में गुंजता रहा है। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन कभी सिर्फ निजी अवसर नहीं रहा, बल्कि बहुजन समाज पार्टी (BSP) के लिए ताकत के

सार्वजनिक प्रदर्शन का दिन बन चुका था। 2000 के दशक में यह तारीख लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में विशाल रैलियों, शक्ति प्रदर्शन और वफादारी के संदेशों के साथ मनाई जाती थी, जिनकी गूंज राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी यूपी फतह करने के लिए हर जिले में रोड-शो और सभा करने की रणनीति बना रही है। पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद इस रणनीति में फ्रंट पर भूमिका निभाएंगे। मायावती भतीजे आकाश आनंद के सहारे चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता पर ब्रेक लगाना चाहती हैं। दूसरी ओर, वह आकाश को सक्रिय करके बसपा कार्यकर्ताओं में उनकी स्वीकार्यता मजबूत करना चाहती हैं। आकाश प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाएंगे। हर जिले में रैली से ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा। युवाओं को बसपा की तरफ आकर्षित किया जाएगा। बिहार की युवा अधिकार यात्रा की तर्ज पर यूपी में भी इसी तरह की जागरूकता रैली सीरीज चलाई जाएगी। बसपा की इन रैलियों में दलित, मुस्लिम, पिछड़े और ब्राह्मणों को जोड़ने पर फोकस रहेगा। 2027 विधानसभा से पहले मायावती आकाश को पूरे प्रदेश में घुमाकर राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती हैं। खासकर आकाश के माध्यम से वह युवाओं को पार्टी के पाले में लाना चाहती हैं, जो चंद्रशेखर आजाद के साथ चले गए हैं। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बसपा में 1 से 10 नंबर तक मायावती ही चेहरा हैं। इसके बाद किसी दूसरे नेता का नंबर आता है।

राजनीति तक सुनाई देती थी. बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को गौतमबुद्ध नगर के बादलपुर गांव में हुआ था। दलित जाटव परिवार में जन्मी मायावती के पिता का नाम प्रभुदास था, जो गौतमबुद्ध नगर में सरकारी कर्मचारी थे।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की उम्र जिस तेजी से बढ़ रही है, उनका राजनीतिक कद उससे ज्यादा तेजी से घट रहा है। 15 जनवरी, 2026 को मायावती के जीवन के 70 साल पूरे हो गए हैं। इनमें करीब 7 साल बतौर सीएम बीते।

मायावती जब पहली बार सीएम बनीं तो उनकी उम्र 40 के करीब थी। इसके बाद वह तीन बार और सीएम बनीं, लेकिन अपने दम पर एक बार ही बन सकीं। 2007 में यह उनके राजनीतिक जीवन का शिखर था। उसके बाद से उनका चुनावी या राजनीतिक सफर ढलान की ओर ही बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) 206 से एक पर पहुंच गई है। अब 2027 में चुनाव है। फिर 2032 में। तब मायावती की उम्र 80 के करीब होगी। उस समय की संभावनाओं पर बात करना अभी सही नहीं होगा। मायावती आईएएस बनना चाहती थीं, उन्हें नेता बना दिया गया। आईएएस बन कर वह पूरे समाज की सेवा करना चाहती थीं, लेकिन नेता बनीं तो दलित समाज को राजनीति का मुख्य आधार बनाया। इसलिए उन्हें सत्ता के लिए लगातार बैसाखी की जरूरत पड़ी। इसकी खामी समझ कर जब उन्होंने अगड़ी जाति को भी जोड़ा तो पहली बार तो लोगों ने उन्हें आजमाया, लेकिन

दोबारा मौका देने लायक नहीं समझा। मायावती के लिए 'माया मिली, न राम' वाली स्थिति हो गई और यह उनके राजनीतिक सफर के लिए घातक साबित हुआ। मायावती ने अपनी राजनीति का आधार दलित को बनाया, लेकिन अपनी जीवनशैली उनसे एकदम अलग दिखाई। जन्मदिन पर आलीशान पार्टियां करना, मंच पर किसी को जगह नहीं देना, पार्टी के बजाय अपने नाम पर चंदा मांगना आदि काम दलितों की वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाने वाली छवि बनाते रहे। इसका खामियाजा धीरे-धीरे देखने को मिला। मायावती ने व्यक्ति पर फोकस किया, संगठन पर नहीं। बसपा को उन्होंने एक व्यक्ति (खुद) पर केन्द्रित कर चलाया। पार्टी का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में रखा। हर निर्णय खुद लिया। सबसे करीबी पदाधिकारी को भी फेसले लेने का अधिकार नहीं दिया। मायावती ने खुद पर केन्द्रित रख कर बसपा को चलाया और जब किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत महसूस हुई तो परिवार पर ही भरोसा किया। उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का कामकाज सौंपा और अपना 'उत्तराधिकारी' बनाया। हालत यह रही कि उन्हें 'अपरिपक्व' पाने पर हटाया और कुछ ही समय बाद दोबारा बड़ा पद देकर वापस भी बुला लिया। गौरतलब है कि आकाश आनंद बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे हैं। आकाश आनंद 31 साल के हैं। आकाश पहली बार 2017 में सार्वजनिक मंचों पर नजर आए। सबसे पहली बार उनको मायावती के साथ सहारनपुर में एक सभा के दौरान देखा गया। उसके बाद मायावती ने लखनऊ में एक बैठक के दौरान उनका परिचय कराया था।

27 की तैयारी में मायावती ! ब्राह्मणों को दी बड़ी सलाह !



सोशल मीडिया पर आकाश का अकाउंट काफी एक्टिव रहता है और वह युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए काफी कोशिशें भी कर रहे हैं। एक्स पर आकाश आनंद के 184 लाख और फेसबुक पर 53 हजार फॉलोअर्स हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो, उन्होंने बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉ. प्रज्ञा से शादी की है।

अब एक नेता दलितों के बीच से भी उभरा है। चंद्रशेखर रावण। बीएसपी को चंद्रशेखर फेक्टर से निपटने के लिए भी ठोस रणनीति बनानी होगी। बसपा के पास ऐसी कोई विरासत नहीं है, जिसे वह भुना सके। मतदाताओं के बीच पार्टी की पहचान मुख्य रूप से दो ही लोगों के नाम से है- कांशी राम और मायावती। ये दोनों नेता भी अपनी ऐसी छवि नहीं बना सके कि पार्टी विरासत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। कांशी राम की मृत्यु 2006 में हुई। उस साल जन्मे लोग 2027 के चुनाव में पहली बार वोट करेंगे। उन्हें शायद ही कांशी राम याद हों। आकाश आनंद का राजनीति में बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। वह लंदन से पढ़ कर लौटे हैं और राजनीति में नए हैं। उनकी लोगों में कोई साख नहीं है।

मायावती को कांशी राम ने लंबे समय तक राजनीति के लिए तैयार किया, लेकिन आकाश को वैसा कोई गुरु नहीं मिला है। आजकल चुनाव में बड़े पैमाने पर पैसा, कार्यकर्ता और अन्य तरह के संसाधनों की जरूरत होती है। बसपा इस मामले में अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी पीछे नजर आ रही है। लेकिन इस बार फिजा काफी बदली हुई नजर आ रही है। यूपी की चार बार मुख्यमंत्री रहें मायावती 15 जनवरी को 70 साल की हो गईं। पार्टी कार्यकर्ता ने पूरे राज्य में उनका जन्मदिन रजन कल्याणकारी दिवसर के रूप में मनाया। लखनऊ में बसपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। बड़ी संख्या में बसपाई मायावती का जन्मदिन मनाने लखनऊ पहुंचे थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर दोहराया कि बसपा 2027 विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। गौरतलब है कि 2007 विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के सहारे बसपा ने यूपी की सत्ता पर कब्जा जमाया था। अपने परंपरागत दलित वोटों के साथ ब्राह्मण वोटों को साथ लेकर मायावती ने विपक्षी दलों को धाराशायी कर दिया था। ब्राह्मण और दलित सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलों को मायावती एक बार

फिर आजमाने के प्रयास में हैं।

विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन :
2007 में यूपी विधानसभा चुनाव में 40.43 फीसद मत, सीट संख्या-206
2012 में 25.91 फीसद मत, सीट संख्या- 80
2017 में 22.23 फीसद मत, सीट संख्या- 19
2022 में 12.83 फीसद मत, सीट संख्या- 1
2024 लोकसभा चुनाव में 7 फीसद, सीट संख्या-

विशेष: यूपी की सियासत पर नजर रखने वाले बताते हैं कि मायावती और उनके रणनीतिकारों को यह बात समझ में आई कि बहुजन के जरिए वो निश्चित सीटों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन 203 के जादुई आंकड़ों को हासिल करने के लिए समाज के सभी वर्गों को संदेश देना होगा कि वो सबके बारे में सोचती हैं। उस क्रम में प्रदेश की ब्राह्मण आबादी को साधने की कोशिश की गई जिनकी संख्या करीब 12 फीसद है। कई रणनीतिक जानकार भी कह रहे हैं कि इसमें दो मत नहीं कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में बीएसपी प्रमुख को लगने लगा कि प्रदेश का यह समाज जो कभी उनके साथ था वो 19-20 साल बाद ही सही उनके साथ आ सकता है और उनके मदद से उनकी हाथी अपनी चाल चलते हुए सबको रौंद देगी। अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा प्रमुख मायावती ने साफ कहा कि ब्राह्मण हित बीएसपी में ही सुरक्षित है। ऐसे में क्या वो 2007 के सर्वजन फॉर्मूला पर बढ़ने की तैयारी कर रही हैं। अखिलेश यादव के साथ साथ बीएसपी को भी लगने लगा है कि अगर वो ब्राह्मण समाज को अपने पाले में लाने में कामयाब हुए तो निश्चित तौर पर 2027 में कमल नहीं खिल पाएगा। फिलहाल सबके अपने-अपने दावे हैं लेकिन दावों में कितना दम है, इसके लिए अगले साल का इंतजार करना होगा।

UP में CM की कुर्सी

13%

वोटर्स ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश में।

12

जिलों में ब्राह्मण वोटों की संख्या 20% से ज्यादा है।

2007

में BSP की सरकार बनाने में ब्राह्मण वोटर्स की भूमिका अहम थी।



aap

AAM AADMI PARTY



पंजाब दा पॉलिटिक्स.

पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गठबंधन कभी सबसे स्थिर और प्रभावी राजनीतिक प्रयोग माना जाता था। 2020 में किसान आंदोलन के बाद यह गठबंधन टूट गया लेकिन अब यह फिर से सियासी चर्चा का केंद्र बन गया है। 1997 से 2020 तक यह गठबंधन पंजाब की राजनीति में अहम भूमिका निभाता रहा। 1997 में विधानसभा चुनाव में गठबंधन को 117 में से 93 सीटें मिलीं। 2007 और 2012 में भी यह गठबंधन मजबूत स्थिति में रहा और क्रमशः 67 और 68 सीटों पर जीत हासिल की लेकिन 2020 में गठबंधन टूटने के बाद दोनों दलों को लगातार नुकसान हो रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में अकाली दल को सिर्फ 3 सीटें मिलीं जबकि भाजपा को दो सीटें मिलीं। 2024 लोकसभा चुनाव में अकाली दल को एक सीट और भाजपा को शून्य सीटें मिली थीं। शिअद-भाजपा गठबंधन का इतिहास चुनावी दृष्टिकोण से फायदेमंद रहा है, लेकिन अब की राजनीति में यह एक जटिल सवाल बन चुका है। पुराने आंकड़े यह बताते हैं कि गठबंधन से दोनों दलों की ताकत बढ़ती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसके साथ जुड़े खतरे भी कम नहीं हैं। भाजपा पंजाब में 117 सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और वर्तमान में पार्टी 43 सीटों पर मजबूत है।

यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पंजाब में सिख धर्म केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि राजनीतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और सामूहिक पीड़ा से गहराई से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि धर्म से जुड़े मुद्दे अक्सर विकास, रोजगार और शासन जैसे सवालों पर भारी पड़ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाएं हैं। इसके बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए और वरगाड़ी तथा बहबल कलां में

प्रदर्शनकारी सिखों पर पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। पंजाब की राजनीति में लंबे समय तक पंथक सियासत शिरोमणि अकाली दल के इर्द-गिर्द घूमती रही है। सिख पंथ से जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक मुद्दों पर अकाली दल की पकड़ मजबूत मानी जाती थी लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह समीकरण तेजी से बदलता दिख रहा है। अकाली दल का जन्म ही पंथक आंदोलन से हुआ। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन से लेकर एसजीपीसी पर नियंत्रण तक, अकाली दल ने सिख धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की। ग्रामीण पंजाब, खासकर माझा और मालवा के पंथक बहुल क्षेत्रों में अकाली दल लंबे समय तक स्वाभाविक विकल्प रहा। पंजाब के कुल मतदाताओं में करीब 30-35 फीसदी ऐसे हैं, जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पंथक मुद्दों से प्रभावित होते हैं। इनमें से अधिकांश का झुकाव ऐतिहासिक रूप से अकाली दल की ओर रहा।

इस दौर में एक सच यह भी है कि अकाली दल पहले ही नेतृत्व संकट, परिवारवाद और सीमित नेतृत्व विकल्पों से जूझ रहा है। विधानसभा और लोकसभा में उसकी सीटें घटकर बहुत कम रह गई हैं। बेअदबी प्रकरणों में निर्णायक कार्रवाई न होना और युवा पंथक मतदाताओं से भावनात्मक दूरी ने उसकी विश्वसनीयता कमजोर की है। ऐसे में जो पंथक वोटर कभी अकाली दल के साथ खड़ा होता था, अब विकल्प तलाश रहा है। पंजाब की राजनीति में करीब से नजर रखने वाले यह भी कह रहे हैं कि अगर पंथक वोटर (सिख) का केवल 10-15 फीसदी हिस्सा भी अकाली दल से खिसकता है, तो इसका सीधा असर 15-20 विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है। माझा क्षेत्र के अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब,

मोगा, बटिंडा और बरनाला में अकाली दल की पारंपरिक पकड़ कमजोर होने लगी है। पंजाब की पंथक राजनीति अब केवल विरासत से नहीं, बल्कि प्रदर्शन और विश्वसनीयता से तय होगी। यही अकाली दल की सबसे बड़ी परीक्षा है और आम आदमी पार्टी के लिए नया राजनीतिक अवसर। वहीं पंजाब में कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल गुटबाजी और नेताओं का बड़बोलापन है। अभी पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वडिंग अलग नजर आते हैं। विधायक दल नेता प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व सीएम व जालंधर सांसद चरणजीत चन्नी की राह अलग-अलग नजर आती है। पंजाब कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही सरकार बनाने का दम भर रही है, लेकिन 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां पार्टी के पास न तो कोई चेहरा है और न ही कोई सक्रिय नेता।

कांग्रेस पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट में इस बात का पता चला है। बटिंडा शहरी, बटिंडा देहाती, मोड़, मानसा, दिड़वा, भदोड़, अबोहर समेत नौ ऐसी सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई चेहरा नहीं है। 21 के करीब सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी के पास चेहरा तो है, लेकिन वे लंबे समय से सक्रिय नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के नेताओं को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी व छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल ने दो टूक कह चुके हैं कि कांग्रेस का कोई CM चेहरा नहीं होगा। कांग्रेस पंजाब प्रभारी का ये बयान 5 बड़े नेताओं, पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी, प्रदेश प्रधान राजा वडिंग, विधायक दल नेता प्रताप सिंह बाजवा और सांसद सुखजिंदर रंधावा के लिए झटका है। हालांकि इनमें से वडिंग और रंधावा पहले ही सीएम चेहरे का दावा छोड़ चुके हैं। पूर्व कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू पहले ही सक्रिय राजनीति से

बाहर हो चुके हैं। कांग्रेस में चरणजीत चन्नी बिना किसी विवाद के सीएम चेहरे की दावेदारी जता रहे हैं।

शिअद-भाजपा गठबंधन का इतिहास:

1997 विधानसभा चुनाव: 93 सीटें।

2007 विधानसभा चुनाव: 67 सीटें।

2012 विधानसभा चुनाव: 68 सीटें।

वर्तमान स्थिति:

2022 विधानसभा चुनाव:

अकाली दल - 3 सीटें, भाजपा - 2 सीटें

2024 लोकसभा चुनाव:

अकाली दल - 1 सीट, भाजपा - 0 सीटें

विशेष: पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात देखें तो पंजाब में AAP के मुकाबले अभी कांग्रेस ही नजर आती है। अकाली दल ने तरनतारन उपचुनाव और जिला परिषद-ब्लॉक समिति उपचुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दिखाई लेकिन अभी वे बराबरी के मुकाबले में नजर नहीं आते। भाजपा जरूर वोट शेयर बढ़ा रही है लेकिन उसका गांवों में आधार नहीं है। वहीं पंजाब में भाजपा का कोर वोट बैंक शहरी है। कांग्रेस हाईकमान के पास भी ये अच्छा मौका है क्योंकि पंजाब उन राज्यों में से एक है, जहां भाजपा की राजनीतिक पकड़ कमजोर है। ऐसे में यहां कांग्रेस के लिए अवसर ज्यादा हैं।



दमदार हैं देवेंद्र

महाराष्ट्र की सियासत में जब-जब हलचल तेज होती है, एक चेहरा पूरी शिद्दत के साथ उभरता है—देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस का। कभी नागपुर के सबसे युवा मेयर रहे फडणवीस आज न केवल भाजपा के 'संकटमोचक' हैं, बल्कि राज्य की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो चुके हैं। हालिया घटनाक्रमों और 2024 के विधानसभा चुनाव परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनके बिना महाराष्ट्र की सत्ता का समीकरण अधूरा है। अपने 12 साल के सक्रिय राजनीतिक जीवन में महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे और पवार परिवार के वर्चस्व को खत्म करने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह ऐलान कि इस चुनाव के बाद भाजपा के 25 मेयर शपथ लेने जा रहे हैं, महज एक संख्या नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए युग के आरंभ का संकेत है। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में महायुति की बड़ी जीत के बाद मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 'महाराष्ट्र का धुरंधर' बताने वाले बेनर-पोस्टर लगाए गए हैं। नगर निगम चुनावों में बीजेपी की जीत को फडणवीस ने विकास, ईमानदारी और मोदी सरकार की नीतियों पर जनता का भरोसा बताया है। एकनाथ शिंदे के लिए मुंबई ने 16 जनवरी को सबसे बड़ा झटका दिया। जो शिवसेना 2022 से बालासाहेब ठाकरे की विरासत की असली उत्तराधिकारी साबित

करने की कोशिश कर रही थी, वो बीएमसी में 90 सीटों में से केवल 29 जीत सकी। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी ने ठाकरे परिवार के 25 साल पुरानी प्रभुत्व को समाप्त किया। इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की देन बताया जा रहा है। फडणवीस को 'नागपुर का आदमी' कहा जाता रहा है। लेकिन महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजों में बीजेपी ने 29 में से 23 नगर निगमों में जीत हासिल की। यह दर्शाता है कि वे अब पूरे महाराष्ट्र के नेता के रूप में उभरे हैं, अब वो शरद पवार के बाद पहले ऐसे नेता होंगे। देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासित कार्यकर्ता से शुरू हुई थी। नागपुर विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई और बर्लिन से बिजनेस मैनेजमेंट की बारीकियां सीखने वाले फडणवीस ने महज 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर बनकर सबको चौंका दिया था। महानगरपालिकाओं के चुनाव परिणामों ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति का महाचाणक्य साबित कर दिया है। महाराष्ट्र में कभी शिवसेना के छोटे भाई की भूमिका में चलनेवाली भाजपा को उन्होंने न सिर्फ पूरे महाराष्ट्र की सबसे अधिक जनाधार वाली पार्टी बना दिया है। बल्कि 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें धोखा देकर कांग्रेस और राकांपा के साथ सरकार बनानेवाले उद्धव ठाकरे से उनका बीएमसी का किला भी छीन लिया है।

1999 में पहली बार विधायक बनने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी बौद्धिक क्षमता और विधायी बारीकियों पर पकड़ ने उन्हें बहुत जल्द दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व का विश्वासपात्र बना दिया। ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले देवेंद्र फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को नागपुर के गंगाधर फडणवीस और सरिता फडणवीस के घर हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि देवेंद्र फडणवीस की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत इंदिरा कॉन्वेंट से हुई थी लेकिन आपातकाल के दौरान पिता के जेल जाने के कारण उनका यहां से नाम कटवा दिया गया और फिर एडमिशन



सरस्वती विद्यालय में करा दिया गया। लॉ ग्रेजुएट फडणवीस के पास विजनस मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की है। फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस एक सिंगर और सोशल वर्कर हैं। फडणवीस के पिता जनसंघ से बीजेपी में आए थे। विधायक भी रहे। गंगाधर फडणवीस को नितिन गडकरी अपना राजनीतिक 'गुरु' मानते हैं। साल 2014 में जब वे महाराष्ट्र के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बने, तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक ब्राह्मण नेता मराठा बहुल राजनीति में अपनी इतनी गहरी पैठ बना लेगा। 2019 के चुनावों के बाद सत्ता के समीकरण बदले और भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा। उस दौरान 'मी पुन्हा येईन' (मैं फिर वापस आऊंगा) का उनका नारा विरोधियों के लिए उपहास का विषय बना, लेकिन फडणवीस ने इसे एक मिशन बना लिया। महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान उन्होंने 'शेडो सीएम' की भूमिका निभाई और लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरे रखा। 2022 में शिवसेना और 2023 में राकांपा में हुई बड़ी टूट के पीछे फडणवीस की दूरगामी रणनीति मानी जाती है, जिसने भाजपा को फिर से सत्ता की दहलीज पर ला खड़ा किया।

दिसंबर 2024 में फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा। महायुति गठबंधन (भाजपा, शिवसेना-शिंदे और राकांपा-अजित पवार) की इस प्रचंड जीत का मुख्य श्रेय फडणवीस की चुनावी व्यूह रचना को दिया गया। आज वे केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य के सबसे भरोसेमंद सूत्रधार बनकर उभरे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र

फडणवीस ने राज्य के शहरी इलाकों में भाजपा के पुनरुत्थान में एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में उभरते हुए पार्टी को नगर निगम चुनावों में जबरदस्त जीत दिलाई और यह साबित किया कि पार्टी आलाकमान की कम से कम भागीदारी के बावजूद वह ऐतिहासिक जनादेश दिला सकते हैं। नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदर्शन ने

फडणवीस का कद और बढ़ा दिया है क्योंकि इस चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व की न्यूनतम भागीदारी रही।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस चुनाव से दूर रहकर राज्य नेतृत्व पर पूरी जिम्मेदारी डाली। फडणवीस ने चुनाव अभियान की अगुवाई की, रणनीति बनाई और उम्मीदवारों का चयन किया, जो इस शानदार जीत के लिए निर्णायक साबित हुआ। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को कमजोर करने के लिए स्थानीय नेताओं को पार्टी में शामिल करने की रणनीति भी अपनाई। पूर्व कांग्रेस विधायक कुनाल पाटिल (धुले) और कैलास गोरंट्याल (जालना) के भाजपा में शामिल होने से निकाय चुनावों में जीत सुनिश्चित हुई और पहली बार भाजपा विधायक राहुल आवडे को इचलकरंजी नगर निगम में जिम्मेदारी सौंपी गई।

सीएम फडणवीस ने नागपुर महानगरपालिका में भी अपनी पकड़ मजबूत रखी, जिससे उनकी स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई। नगर निकाय चुनावों ने फडणवीस की नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक निर्णय क्षमता को उजागर किया है, और ये परिणाम विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद महत्वपूर्ण हैं। नगर निकाय चुनावों को फडणवीस के नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण परीक्षण माना जा रहा था। चुनावी हार, अपमान और सत्ता से बाहर होने के बाद भी जिस तरह उन्होंने दमदार वापसी की, उसने उन्हें 'महाराष्ट्र का नया चाणक्य' बना दिया है। भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है।





कमजोर होते कम्युनिस्ट..

लकीर की फकीरी की तरह भारत के कम्युनिस्टों ने कार्ल मार्क्स के उस कथन का अक्षरशः अनुपालन करते हुए धर्म को 'अफीम का नशा' मान लिया। जबकि सोवियत संघ में कभी कम्युनिस्ट सरकार और चर्च के बीच कोई टकराव देखने को नहीं मिला। साम्यवाद का काबा माना जाने वाला सोवियत संघ जब भरभराकर ढह गया, तब यह कहा गया कि विश्व की पूंजीवादी शक्तियों ने पूरी ताकत के साथ समाजवाद का अंत कर दिया। उस प्रतिकूल दौर में भी भारत में कई राज्य ऐसे थे जहां कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व कायम रहा, लेकिन समय के साथ उनका आधार भी दरकता जा रहा है। आज बंगाल फिर त्रिपुरा के बाद केवल केरल ही आखिरी किला बचा है। इस साल केरल में चुनाव होने हैं जहां कांग्रेस की जीत की बड़ी संभावना है। मतलब कम्युनिस्टों के हाथ से केरल भी जाने वाला है। एक जमाने में कम्युनिस्ट होने का अर्थ आधुनिक होना माना जाता था। जब लोग मुश्किल से टाइपराइटर का इस्तेमाल कर पाते थे, तब कम्युनिस्ट पार्टियों के दफ्तरों में आधुनिकतम टाइपिंग और साइक्लोस्टाइल मशीनें, छापेखाने और प्रकाशन हुआ करते थे। मगर समय के साथ कम्युनिस्टों ने अपने तंत्र को अपडेट नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि बेहतर माना जाने वाला कम्युनिस्टों का संगठन निर्माण कौशल धीरे-धीरे परंपरागत और अप्रसांगिक हो चला है, जबकि उसके मुकाबले खड़े खेमों में आधुनिक तकनीक पर आधारित सांठनिक ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टियों में नेतृत्व का संकट भी पैदा हो गया है।

पिछले ही साल 2025 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के

गठन के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। CPI भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को आधुनिक कानपुर में हुई थी। वर्तमान में, इसके पास लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 2 सदस्य हैं, जो तमिलनाडु, केरल और मणिपुर में राज्य पार्टी का ECI दर्जा बनाए रखता है। 1950 से 1960 के दशक में, CPI भारत में प्राथमिक विपक्षी दल के रूप में कार्य करती थी।

एमएन रॉय और अन्य लोगों ने पार्टी की शुरुआत की थी। वे मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारों का पालन करते थे। पार्टी ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने और समाजवादी भारत बनाने के लिए क्रांति चाहती थी। शुरुआत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने कांग्रेस के साथ सहयोग किया। लेकिन जल्द ही मतभेद उभर आए। सीपीआई हिंसक क्रांति में विश्वास करती थी, जबकि कांग्रेस अहिंसक विरोध चाहती थी। सीपीआई ने कांग्रेस पर अंग्रेजों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। ब्रिटिश सरकार ने कई कम्युनिस्ट नेताओं को जेल में डाल दिया। उन्होंने 1929 और 1934 में दो बार पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। पार्टी ने 1957 में केरल में संयुक्त मोर्चा सरकार बनाने के लिए अन्य वामपंथी समूहों के साथ भी हाथ मिलाया। आजादी के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रम अधिकारों, भूमि सुधारों और आर्थिक सुधारों के विरोध पर ध्यान केंद्रित किया। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चुनावी सफलता हासिल नहीं कर सकी। लेकिन इसने केरल और बंगाल जैसे राज्यों में अन्य वामपंथी दलों के साथ कई

मिलकर कई सरकारें बनाईं। एक सदी के दौरान कई धड़ों और धाराओं में बंट चुकी कम्युनिस्ट पार्टी आज भले अपने अवसान पर दिखती है, लेकिन इस समाज को दिए उसके योगदानों और शहादतों की दास्तान बहुत लंबी और बड़ी है, जिससे युवा पीढ़ी अधिकांशतः अनजान है। 1957 में सीपीआइ ने पहले चुनावों में जीत हासिल करके सरकार बनाई। 5 अप्रैल 1957 को ईएमएस नम्बूद्रीपाद ने केरल के पहले मुख्यमंत्री के



तौर पर शपथ ग्रहण किया था। सीपीआइ(एम) और सीपीआइ 1967-1969 और 1969-1970 के दौरान थोड़े समय के लिए बनी युनाइटेड फ्रंट सरकारों में शामिल थीं। 1977 में वाम मोर्चा, जिसमें सीपीआइ(एम), सीपीआइ और अन्य वामपंथी पार्टियां शामिल थीं, को चुनाव में जीत हासिल हुई और उनकी सरकार बनी। ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 साल तक कम्युनिस्टों की सरकार रही। इस वर्ष अपने 100 साल पूरे करने वाला भारतीय कम्युनिज्म (भारतीय साम्यवाद) एक अधूरी परियोजना है। कभी युवाओं को आकर्षित करने वाली इस विचारधारा में आज युवाओं का अकाल दिखता है जिन्हें आकर्षित करने के लिए नेतृत्व का अभाव एक बड़ी वजह है। वामदल जिन वर्गों के हक में राजनीति करने का दावा करते हैं वे कभी नेतृत्व की भूमिका में नहीं आ पाते हैं। समय के साथ-साथ भारत की लगभग सभी कम्युनिस्ट पार्टियों के जनसंगठन कमजोर हो गए और पार्टी नेतृत्व ने इसे नजरअंदाज कर दिया।

नतीजा यह हुआ पार्टी की एक समय पार्टी की ताकत अब उसकी कमजोर कड़ी बन गई। वहीं पार्टी और ट्रेड यूनियन में जो तालमेल होना चाहिए, समय के साथ उसमें भी भारी कमी देखने को मिली है। इसका पार्टी संगठन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इनके अलग-अलग धड़े भी भ्रमित करने का काम करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआइ) की स्थापना 1925 में हुई। इसके बाद 1964 में वैचारिक मतभेद के कारण पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन

हुआ और माकपा का जन्म हुआ। इसके बाद नक्सलवादी समर्थक नेताओं ने 'ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी' (एआइसीसीआर) का गठन किया और वे सीपीएम से अलग हो गए। फिर बाद में आंध्र प्रदेश में भी तेलंगान सशस्त्र विद्रोह समर्थक नेताओं का अलग धड़ा बना। फिर सीपीआइ (एम एल) बना। इस तरह समय-समय पर बनीं अनेक कम्युनिस्ट पार्टियां आज अस्तित्व में हैं। यही भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की कमजोरी भी है। ये पार्टियां अक्सर एक दूसरे से अलग खड़ी दिखती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भारत के कम्युनिस्ट आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गए हों। टूटा हुआ मनोबल साफ दिखाई देता है। विरोधी खेमा लगातार कम्युनिस्टों के बारे में दुष्प्रचार कर रहा है कि ये भारत विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, नास्तिक और धर्म विरोधी हैं, विदेशी विचारधारा वाले हैं और यहां तक कि विकास और राष्ट्रवाद के विरोधी भी हैं। इस दुष्प्रचार के विरोध में वे अपने पुराने गौरवशाली अतीत से कई मिसालें दे सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी तरह समर्पण कर दिया।

हालत यहां तक खराब हो चुकी है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर कम्युनिस्ट पार्टियों के बयान तक जारी नहीं हो पाते हैं। आम जनमानस में कम्युनिस्टों के बारे में नास्तिक, धर्म विरोधी और विदेशी विचारों के अनुयायी जैसी छवि जो शुरुआत में ही बन गयी थी, वह आज भी कायम है। साथ ही उनकी आंदोलन वाली भावना पर भी वक्त के साथ जंग लग गया है। उनका अति-आत्मविश्वास भी उनके डूबने की

अहम वजह रहा। त्रिपुरा में भाजपा की जीत कोई रातोंरात हुआ चमत्कार नहीं है। वर्ष 2014 में भाजपा के नेतृत्व में राजग सरकार बनने के बाद से भाजपा ने पूर्वोत्तर पर खास ध्यान देना शुरू किया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) दोनों ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए, जो भारत की दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधाराओं के दो ध्रुवीय संगठन हैं, जिनकी स्थापना 1925 में हुई थी, लेकिन उनकी यात्रा और वर्तमान स्थिति काफी भिन्न है, जिसमें RSS का प्रभाव बढ़ा है जबकि CPI हाशिये पर चली गई है। अपने 100 साल पूरे होने पर, RSS एक विशाल सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन के रूप में उभरा है, जिसके लाखों सदस्य और सहयोगी संगठन हैं, और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के माध्यम से राजनीति में इसका प्रभाव बढ़ा है।

वहीं दूसरी ओर, CPI और उसके सहयोगी दल (जैसे CPI(M)) राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और हाशिये पर चले गए हैं। RSS और CPI दोनों 1925 में शुरू हुए, लेकिन 100 साल बाद, RSS एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है, जबकि CPI का प्रभाव कम हो गया है, जिससे भारत के राजनीतिक परिदृश्य में दक्षिणपंथी विचारधारा का काफी दबदबा बढ़ा है। RSS (संघ) से वैचारिक तौर पर जुड़ी BJP सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। संघ से जुड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। यहां तक कि जिन मजदूरों का नारा देकर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, वहां भी संघ का वर्चस्व है। संघ से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे

बड़ा मजदूर संगठन है। ताज़ा आंकड़े के अनुसार देश भर में संघ की शाखाओं की संख्या 83,129 है। शताब्दी वर्ष में संघ का लक्ष्य शाखाओं की संख्या बढ़ाकर 1 लाख तक पहुंचाना है। RSS शिक्षा, सेवा और आपदा राहत के रचनात्मक मॉडल पर काम करता है जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों का मॉडल आंदोलन, हड़ताल और धरने का है। यही वो कारण हैं जिसकी वजह से 100 साल बाद 2 संगठन आज बिल्कुल अलग-अलग स्थितियों में हैं।

एक जहां सफलता के शिखर पर है, तो दूसरा पतन के कगार पर खड़ा है।



“हलाल” होते हिंदू...



बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। फिर भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्याओं का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश में 17 फरवरी को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले कट्टरपंथियों का आतंक जारी है। बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम एक दर्जन हिंदुओं की हत्या की गई है। फरवरी में होने वाले इलेक्शन से पहले एक से बढ़कर एक खतरनाक भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं।

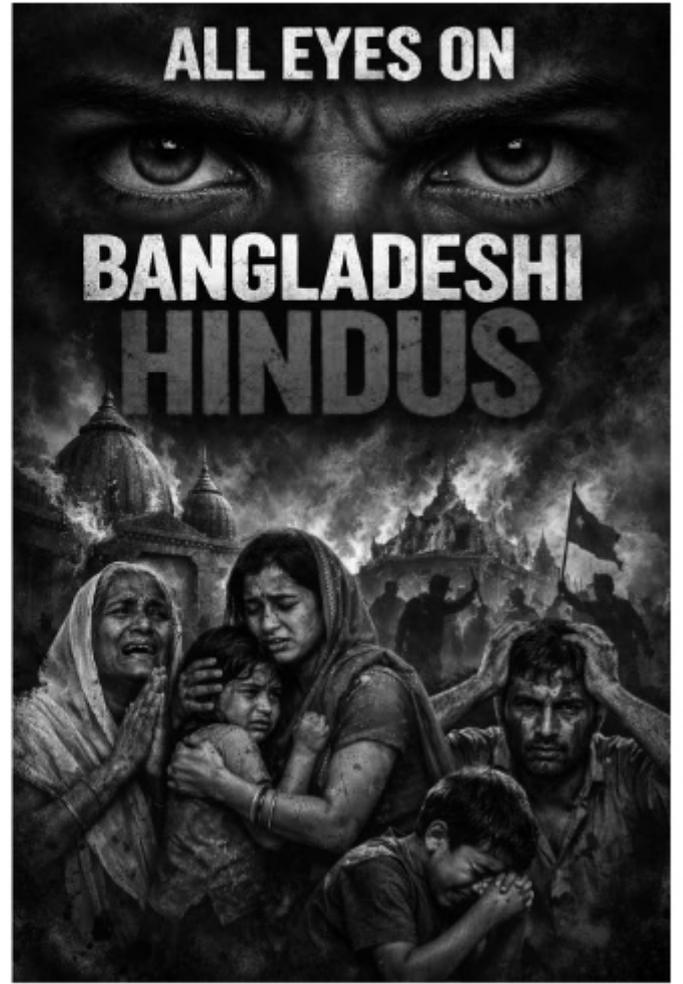
मोलानाओं ने मानो हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हुआ है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं। बांग्लादेश में मोलाना अपनी सभाओं में हिंदुओं के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। हाल के हफ्तों में दर्जनों हिंदुओं के घरों को तोड़ दिया गया है और कई घरों को बाहर से बंद कर आग लगा दिया गया है। कई देशों ने बांग्लादेश में हिंदुओं से होने वाली हिंसा की आलोचना की है, लेकिन मोहम्मद युनुस की अंतरिम सरकार लगातार ऐसे तत्वों का समर्थन कर रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। बांग्लादेश में यह

धारणा व्यापक रूप से प्रचलित है कि भारत ने हसीना के शासन को समर्थन दिया था। हसीना और उनकी धर्मनिरपेक्ष अवामी लीग पार्टी को देश की अन्य प्रमुख राजनीतिक ताकतों, जैसे बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी की तुलना में हिंदू अल्पसंख्यक (जो जनसंख्या का 10 प्रतिशत है) के प्रति अधिक सहानुभूति रखने वाला माना जाता है। लेकिन बांग्लादेश में अधिकतर हिंदुओं का साफ कहना है कि शेख हसीना के शासन में भी हिंदू सुरक्षित नहीं थे। हिंदुओं राजनीतिक मोहरों की तरह इस्तेमाल किया गया। अल्पसंख्यक अधिकार समूह, बीएचबीसीयूसी ने इससे पहले जून 2023 और जुलाई 2024 के बीच हसीना प्रशासन के दौरान हुई 45 हत्याओं की रिपोर्ट दी थी, जिनमें से अधिकांश हिंदू थे। 2021 में, दुर्गा पूजा के दौरान और उसके बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक परिवारों और मंदिरों पर भीड़ द्वारा किए गए हमलों के बाद, मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, बांग्लादेश में वर्षों से अल्पसंख्यकों के घरों और पूजा स्थलों पर व्यक्तियों के खिलाफ इस तरह के बार-बार होने वाले हमले,

सांप्रदायिक हिंसा और तोड़फोड़ यह दर्शाते हैं कि राज्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा है। "भारत ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पर चिंता जताई है। पिछले सप्ताह भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। बांग्लादेश के पंचगढ़, दिनाजपुर, बोगुरा, रंगपुर, शेरपुर किशोरगंज, सिराजगंज, मुगरा, नरेल, पश्चिम जशोर, पटुआखली, दक्षिण-पश्चिम खुलना, मध्य नरसिंगड़ी, सतखीरा, तंगैल, फेनी चटगांव, उत्तर-पश्चिम लक्खीपुर और हबीगंज जैसी जगहों पर कट्टरपंथियों का आतंक जारी है। वह यहां रहने वाले हिंदुओं पर न सिर्फ हमले कर रहे हैं बल्कि उनकी संपत्तियों को भी लूट कर ले जा रहे हैं। बांग्लादेश में रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय खासकर हिन्दू इन दिनों डर से साये में रहने को मजबूर है।

लगभग 17 करोड़ की आबादी वाले मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में 2024 के सत्तापलट के बाद से हालात अस्थिर बने हुए हैं। इस्लामी संगठनों की सक्रियता बढ़ने से अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। बांग्लादेश में इस समय 91 फीसदी मुसलमान हैं, 8% से भी कम हिंदुओं की आबादी है। अब हैरानी इस बात की नहीं है कि हिंदू सिर्फ 8 फीसदी के करीब हैं, चिंता का विषय यह है कि हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में साल दर साल घटती जा रही है। बांग्लादेश में 1971 में हिंदुओं की आबादी 13.5 प्रतिशत थी, 1991 तक आंकड़ा 10 फीसदी के आसपास पहुंच गया और अब यह 8 फीसदी से भी नीचे जा चुका है।

बांग्लादेश में 1947 तक 40 फीसद से कहीं अधिक हिंदू जनसंख्या निवास कर रही थी। इन सबके बीच ये खबर राहत देने वाली है



कि दुनिया भर से इन अभागे हिंदुओं के लिए स्वर उठे हैं। भारत नेपाल सहित कई देशों में प्रदर्शन भी चालू है। दुनिया भर की कई जानी मानी हस्तियों ने इसपर आपत्ति व्यक्त की है। वैसे इस पूरे प्रकरण में पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया बेहद आपत्तिजनक है। अमेरिकी प्रशासन का ये कहना कि हम बांग्लादेश के आवाम के साथ हैं, वास्तव में इन दंगाइयों के मनोबल को बढ़ाने वाला है। जबकि प्रसिद्ध पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स का हिंदू विरोधी हिंसा को पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ आक्रोश बताना बेहद आपत्तिजनक है।

पड़ोस(बांग्लादेश)में हो रहा हिंदू नरसंहार निश्चित ही भारत को भी प्रभावित करेगा। वहीं रही सही कसर तेज गति पलायन और बड़ी संख्या में होने वाले घुसपैठो से भी होने वाली है। इससे पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठनों को सुरक्षित जगह और ग्रेटर बांग्लादेश जैसे मुद्दों को हवा भी मिलेगी। इसे रोकना जाना बेहद कठिन होगा, क्योंकि भारत बांग्लादेश सीमा करीब 4096 किलोमीटर लंबी है।



खनन पर खामोश

अरावली सिर्फ पत्थर नहीं, राजस्थान का 'फेफड़ा' है। आंकड़ों में साफ है कि राजस्थान में अरावली का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा फेला है और वही अवैध खनन की सबसे अधिक मार झेलने को मजबूर है।

अरावली बचाने को लेकर हाल के दिनों में आंदोलन हुए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को बदलना पड़ा और केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में खनन कार्य के लिए दिए गए सभी पट्टों पर रोक लगा दी है। अरावली के अस्तित्व को लेकर राजस्थान से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम और दिल्ली तक में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। दक्षिण राजस्थान में सबसे अधिक आंदोलन हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अरावली क्षेत्र में लगातार निर्माण और खनन से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है, जिससे जलस्तर गिर रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि अरावली को बचाने के लिए टोस और सख्त कदम उठाए जाएं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि यह मान लेना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊँचाई वाली हर ज़मीन पर खनन की इजाजत होगी।

सरकार का कहना है कि अरावली पहाड़ियों या श्रृंखलाओं के भीतर नए खनन पट्टे नहीं दिए जाएँगे और पुराने पट्टे तभी जारी रह सकते हैं, जब वे टिकाऊ खनन के नियमों का पालन करें।

पर्यावरण मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 'अभेद्य' क्षेत्रों, जैसे कि संरक्षित जंगल, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और आर्द्रभूमि में खनन पर पूरी तरह रोक है। अरावली पर्वत श्रृंखला पूरे उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। हालांकि यह भी कहना गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के लिए एक

अरावली पर्वत श्रृंखला

क्यों खास?

लंबाई 800+ किमी राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात

सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर (1722 मीटर)



प्राकृतिक जीवन रक्षक कवच की तरह काम करती है। दिल्ली-एनसीआर और गंगा के मैदानी इलाकों को रेगिस्तान, प्रदूषण और जल संकट से बचाने में इसकी भूमिका बेहद अहम है।

इस सच से नजरें नहीं चुराई जा सकती कि अवैध कब्जों और खनन की वजह से अरावली की हरियाली कम हो रही है। इससे इसकी 'ग्रीन बैरियर' की ताकत कमजोर पड़ गई है। नतीजतन रेगिस्तान फैलने की रफ्तार बढ़ रही है और उत्तर भारत का पर्यावरण संतुलन खतरे



खतरे में पड़ रहा है। सरकार का कहना था कि अरावली पहाड़ियों या श्रृंखलाओं के भीतर नए खनन पट्टे नहीं दिए जाएँगे और पुराने पट्टे तभी जारी रह सकते हैं, जब वे टिकाऊ खनन के नियमों का पालन करें।

पर्यावरण मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि 'अभेद्य' क्षेत्रों, जैसे कि संरक्षित जंगल, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और आर्द्रभूमि में खनन पर पूरी तरह रोक है। भारत के इतिहास से पहले से 'अरावली पर्वतमाला' का स्वर्णिम इतिहास रहा है। मध्यकालीन इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अरावली के दुर्गम पहाड़ों ने महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध के लिए कैसे सुरक्षित

स्थान दिया। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे प्रसिद्ध किले भी इसी श्रृंखला का हिस्सा हैं। भारत की धरती पर फेली अरावली पर्वत श्रृंखला सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फेली यह श्रृंखला करीब 670 किलोमीटर लंबी है और इसका इतिहास पृथ्वी के बहुत पुराने समय से जुड़ा है। वन विभाग द्वारा अरावली

का हरा-भरा करने के लिए पोधारोपण किया जा रहा है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली में किसी भी तरह के खनन कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी खनन माफियाओं द्वारा समय-समय पर अरावली में अवैध खनन किया जाता रहा है। राजस्थान के लिए अरावली पर्वतमाला जहां एक ओर जीवनरेखा है, वहीं क्षेत्रफल में देश के सबसे बड़े राज्य के लिए बड़ा संकट बनती जा रही है। इसके बीच अगर अरावली कमजोर हुई, तो उसका असर सिर्फ पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि समूचे राजस्थान और राजधानी दिल्ली तक को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।



कैसे बचे अरावली?

युवा चेतना ही राष्ट्र चेतना: विकास सिंह “भोले”

स्वामी विवेकानंद नन्द की जयंती(राष्ट्रीय युवा दिवस) के मौके पर कानपुर-अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, आलोक सिंह ने लाजपत भवन, मोतीझील में विकास सिंह 'भोले' द्वारा आयोजित 'युवा चेतना-2026' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय "सजग सोच सुरक्षित भविष्य" था, जो साइबर सुरक्षा के महत्व पर केंद्रित था। एडीजी आलोक सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में युवा शक्ति को साइबर अपराध के विरुद्ध सबसे बड़ी ढाल बताया। एडीजी आलोक सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि, "डिजिटल दुनिया में सावधानी ही आपकी सुरक्षा है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि साइबर अपराधों पर प्रभावी रोक केवल 'युवा चेतना' के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे साइबर अपराध के खिलाफ "आज से ही जागरूक बनें"। उन्होंने जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण मंत्र दिये। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत और जटिल पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए और किसी भी संदिग्ध लिंक या ई-

मेल के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। इस महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे रघुवीर लाल पुलिस आयुक्त, कानपुर कमिश्नरेंट, श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात, रक्षित टंडन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इनके अलावा, पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं युवा शक्ति भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

अकबरपुर सांसद देवेन्द्र सिंह भोले के बेटे विकास सिंह 'भोले' द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का

उद्देश्य कानपुर के युवाओं को डिजिटल खतरों से बचाना और उन्हें एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण प्रदान करने के लिए प्रेरित करना था। राष्ट्रीय युवा दिवस पर हुए इस कार्यक्रम पर स्वामी विवेकानंद नन्द युवा समिति के अध्यक्ष विकास सिंह भोले ने स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देने और साइबर युग में सुरक्षित रहने का संदेश दिया। विकास सिंह भोले ने खचाखच भरे लाजपत भवन हाल में मौजूद युवाओं और गणमान्य लोगों के बीच अपने भाषण में कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की 'नींव' होते हैं। इसी युवा शक्ति को समर्पित राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारत की युवा शक्ति को समर्पित है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्में स्वामी विवेकानंद ने सदैव युवाओं को प्रेरित किया। यह दिन युवाओं को उनके विचारों और ऊर्जा को देश के विकास में लगाने के लिए प्रेरित करता है। नशा मुक्त युवा ही देश की तकदीर बदल सकता है।



विकास सिंह भोले ने जोर देकर कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीएंगे, नशामुक्त समाज बनायेंगे और अपने भीतर छिपी शक्ति और विवेक को पहचानेंगे, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करेंगे तथा अपनी ऊर्जा से समाज और देश की उन्नति लगाएंगे। युवा चेतना 2026 कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए विकास सिंह 'भोले' ने कहा कि भारत में हर साल 12 जनवरी का दिन ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा के नाम होता है। यह केवल एक कैलेंडर तारीख नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके युवाओं की सोच और उनकी कार्यक्षमता पर निर्भर करती है।

स्वामी विवेकानंद युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणास्रोत रहे हैं। उनका मानना था कि युवा शक्ति ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। युवा चेतना को जागृति करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करना ही विवेकानंद युवा समिति का एकमात्र ध्येय है।

राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत 1984 में हुई थी। भारत सरकार ने महसूस किया कि स्वामी विवेकानंद का दर्शन और उनके आदर्श भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हो सकते हैं। इसलिए साल 1984 में भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस का सबसे पहला आयोजन 12 जनवरी 1985 को किया गया।





बीएमसी संभालेगी बीजेपी..

मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के ऐतिहासिक चुनावी नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। देश ही नहीं पूरे एशिया की सबसे अमीर और बड़ी महानगर पालिका बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। सिर्फ बीएमसी ही नहीं महायुति ने महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 25 निगमों में भगवा परचम लहराकर ठाकरे बंधुओं के साथ पूरे विपक्ष सफाया कर दिया है। तीन दशकों से मुंबई की सत्ता पर काबिज 'मातोश्री' का वर्चस्व आखिरकार समाप्त हो गया है। बीजेपी पहली बार देश की सबसे बड़ी महानगरपालिका BMC की सत्ता संभालेगी। पिछली बार महज 2 सीटों से चुकी बीजेपी ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उद्धव सेना से दूरी के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मिशन मुंबई को सफल बनाने के लिए खुद कमान संभाली थी। सीट बंटवारे पर सहमति बनाकर शिंदे और आठवले को साथ लिया। चुनाव से ठीक पहले अमित साठम को मुंबई BJP की कमान दी गई। राज ठाकरे से गठबंधन का उद्धव ठाकरे को अपेक्षित फायदा नहीं मिला।

मराठी वोट एकत्रित करने के चक्कर में गैर-मराठी वोट पार्टी से छिटक गए। बीजेपी का विकल्प बनने का ख्वाब देख रही पार्टी पिछली बार का 84 सीटों का प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी। मुंबई में कांग्रेस का कोर

वोट बैंक अब भी है। पार्टी ने अकेले चुनाव लड़कर संगठन को जिंदा करने की पहल की। हालांकि, सीटों के लिहाज से उसे पुरानी सफलता नहीं मिली। लेकिन अलग-अलग इलाकों से उसके नगरसेवक चुनकर आए। इससे भविष्य के कांग्रेस के मजबूत होने के संकेत हैं। एक तरफ फडणवीस मुंबई के नए 'सुल्तान' बनकर उभरे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने हार के बावजूद अपनी कद्दावर सियासी साख साबित कर दी है। 1997 के बाद पहली बार हारने के बावजूद उद्धव ठाकरे मुंबई के 'मराठी मानूस' के दिलों में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहे हैं। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने मुंबई की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वह ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसका भाजपा को दशकों से इंतजार था। 1997 से बीएमसी की सत्ता पर काबिज ठाकरे परिवार का किला अब ढह चुका है। महायुति ने 227 सीटों में से बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है।

16 जनवरी को घोषित हुए परिणामों में भाजपा-शिंदे गठबंधन (महायुति) ने प्रचंड बहुमत हासिल कर ठाकरे परिवार के 'आखिरी किले' को ध्वस्त कर दिया है। बीएमसी चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव स्पष्ट रूप से शिवसेना (यूबीटी) की ओर होने के बावजूद

BMC चुनाव 2026: अंतिम परिणाम पार्टी-वार सीटों का विवरण

पार्टी / गठबंधन	सीटें जीतीं
भारतीय जनता पार्टी (BJP)	89
शिवसेना (एकनाथ शिंदे)	29
शिवसेना (UBT)	65
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	24
AIMIM	08
MNS (राज ठाकरे)	06
NCP (अजीत पवार)	03
समाजवादी पार्टी (SP)	02
NCP (शरद पवार)	01
कुल सीटें	227

महायुति (BJP + शिंदे गुट) = 118 सीटें (बहुमत पार)

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने छह सीटों पर जीत हासिल की है। दशकों से मुंबई के दादर, परेल और लालबाग जैसे क्षेत्र शिवसेना (यूबीटी) का गढ़ माने जाते थे। लेकिन इस बार उद्धव-राज के एक साथ आने के बावजूद 'मराठी मानुष' का वोट दो हिस्सों में बंटता दिखाई दिया। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के प्रभाव वाले वर्ल्ड और गिरगांव जैसे क्षेत्रों में भाजपा की मदद से सेंधमारी की, जिससे 'ठाकरे ब्रांड' की पकड़ ढीली पड़ गई है। विशेषकर गुजराती, उत्तर भारतीय और मध्यम वर्गीय मराठी मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में एकतरफा मतदान किया। दूसरी ओर शिवसेना का दो फाड़ होना उद्धव ठाकरे के लिए सबसे घातक साबित हुआ।

कोस्टल रोड और मुंबई मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स का श्रेय भाजपा-शिंदे सरकार ले जाने में सफल रही।

मातोश्री की महिमा: 1997 से 2022 तक शिवसेना के 12 मेयर रहे। 1997 में मिलिंद वैद्य ने लंबे समय बाद शिवसेना के मेयर पद हासिल किया था। इसके बाद 2022 तक यह पद शिवसेना के पास ही रहा। किशोरी पेडनेकर निवर्तमान मेयर रहीं। उनका कार्यकाल 2022 में खत्म हुआ। इस बीच में विशाखा राउत, नंदू सटम, हरेश्वर पाटिल, महादेव देवले, दत्ता दलवी, शुभा राउल, श्रद्धा जाधव, सुनील प्रभु, स्नेहल आंबेकर, विश्वनाथ महादेश्वर मेयर बने थे।

महाराष्ट्र की राजनीति के लिए 'मिनी विधानसभा' कहे जाने

वाले 29 महानगरपालिकाओं के चुनावी दंगल में बीजेपी ने बाजी मार ली है। 1441 वार्डों में जीत के साथ बीजेपी पहले नंबर पर है। वहीं मुंबई बीएमसी में बीजेपी गठबंधन ने बहुमत से ज्यादा 118 वार्ड जीतकर सभी का चौका दिया है। वहीं उद्धव राज गठबंधन मिलकर भी 71 सीटें ही ला सके। वहीं कांग्रेस ने 24 सीटें हासिल की हैं। सबसे बुरा प्रदर्शन शरद पवार की एनसीपी का रहा। पार्टी ने सिर्फ 1 वार्ड ही जीता है।

ये चुनाव न केवल स्थानीय निकायों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की सत्तासीन महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) के लिए अपनी जमीनी पकड़ साबित करने का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा था। लेकिन MVA के लिए हर तरफ बुरी खबर ही मिली।

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026

पार्टी	सीट
BJP	1420
शिवसेना	375
कांग्रेस	329
शिवसेना (उद्धव)	175
NCP	160
NCP (SP)	40
MNS	13
वंचित बहुजन आघाड़ी	40
AIMIM	125
अन्य	165

कुल सीट : 2869

BMC का बजट किन राज्यों से ज्यादा?

बीएमसी	₹74,427 करोड़
हिमाचल प्रदेश	₹58,514 करोड़
अरुणाचल प्रदेश	₹39,842 करोड़
त्रिपुरा	₹31,412 करोड़
गोवा	₹28,162 करोड़
सिक्किम	₹16,196 करोड़

निशाना साधेंगे “नवीन”

करीब 18 करोड़ सदस्य, देश के हर जिले में अपना ऑफिस, मजबूत जमीनी कैडर, 20 राज्यों में सरकारें, ये बातें BJP को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाती हैं। बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नबीन ने 20 जनवरी को BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल लिया। बीजेपी के 12वें और 45 साल के नबीन पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनसे पहले अमित शाह 49 साल की उम्र में पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चुने गए थे। बीजेपी का अध्यक्ष बनने वाले नबीन बिहार के पहले नेता हैं। वो बीजेपी के पहले कायस्थ अध्यक्ष भी हैं। नबीन ऐसे समय अध्यक्ष बन रहे हैं जब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं, जहां बीजेपी आज तक सरकार नहीं बना पाई है। वहीं बीजेपी के सामने असम में तीसरी बार और पुडुचेरी में दूसरी बार सरकार बनाने की चुनौती है।

पिछले कुछ सालों में धर्म और मंदिर की राजनीति छोड़कर जाति की राजनीति की ओर कदम बढ़ा रही बीजेपी के लिए नए राजनीतिक माहौल में सामंजस्य बिठाना भी बड़ी चुनौती होगी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल दिलाना है। क्योंकि बीजेपी 2024 के चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य होने के बाद भी काफी पीछे रह गई थी। नबीन को यूपी में सपा के पीडीए की काट खोजनी होगी। साल 2029 का लोकसभा चुनाव नए परिसीमन और महिला आरक्षण के साथ कराया जाएगा। ऐसे में नई और बदली हुई परिस्थितियों में नबीन को पार्टी की रणनीति तैयार करनी होगी।

ध्यान देने वाली बात यह है कि भाजपा में अब तक 11 नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें लालकृष्ण आडवाणी तीन बार अध्यक्ष

बने, जबकि राजनाथ सिंह ने दो बार यह जिम्मेदारी संभाली। नितिन नबीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्रों के बराबर सुविधाएं देती है। पार्टी कार्यक्रमों और यात्रा के दौरान, सभी खर्च और व्यवस्थाएं पार्टी द्वारा कवर की जाती हैं। साथ ही अध्यक्ष को देशभर में बिना किसी रुकावट के आने-जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और सुविधाएं दी जाती हैं। इस तरह, नितिन नबीन को सिर्फ संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्रों के बराबर सुविधाएं देती है। पार्टी कार्यक्रमों और यात्रा के दौरान, सभी खर्च और व्यवस्थाएं पार्टी द्वारा कवर की जाती हैं। साथ ही अध्यक्ष को देशभर में बिना किसी रुकावट के आने-जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और सुविधाएं दी जाती हैं। इस तरह, नितिन नबीन को सिर्फ संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्रों के बराबर सुविधाएं, समर्पित टीम, सुरक्षा और



नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष बनेंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था। जैसे पीएम मोदी ने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर चौकाया है वैसे ही नितिन नवीन की टीम भी चौंकाएगी। खबर यह है कि पूरे बीजेपी का बदलना तय है। ऊपर से नीचे तक लगभग सब बदले जा सकते हैं। नए नेताओं को केंद्रीय टीम में जगह मिल सकती है। लंबे समय से संगठन में मजे कर रहे नेताओं को कार्यकर्ता बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि मीडिया की पूरी टीम बदल जाएगी। प्रवक्ताओं में नए चेहरों को जगह मिल सकती है।

इतिहास: बीजेपी के सियासी इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता दिग्गज नेता पार्टी की कमान संभाल चुके हैं। 1980 में जनसंघ के बाद उभरी भाजपा में 12 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये सभी निर्विरोध चुने गए हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी की कमान लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाली। लाल कृष्ण आडवाणी तीन बार (1986-1990, 1993-1998, 2004-2005) पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आडवाणी के बाद डॉ. मुरली मनोहर जोशी (1991-1993) ने पार्टी की कमान संभाली थी। कुशा भाऊ ठाकरे का कार्यकाल पहली पूर्ण एनडीए सरकार का था। बंगारु लक्ष्मण का 2000-2001 तक छोटा सा कार्यकाल रहा। वे पहले दलित अध्यक्ष थे। इसके बाद के. जाना कृष्णमूर्ति (2001-2002) ने पार्टी की कमान संभाली। के. जाना कृष्णमूर्ति के बाद पार्टी ने वेंकैया नायडू पर भरोसा जताया था। साल 2005 में राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वह दो बार (2005-2009, 2013-2014) संगठन के अध्यक्ष बने थे। नितिन गडकरी (2010-2013) पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। साल 2014 में अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अमित शाह के बाद जगत प्रकाश नड्डा साल 2020 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब भाजपा की कमान नितिन नवीन के हाथों में है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भाजपा बीते कुछ समय से युवा चेहरों को आगे बढ़ाने की तरफ है। भाजपा और पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के लिए 55 वर्ष से कम उम्र के नेताओं के नेताओं को तरजीह दी है। कई राज्यों में ऐसे नेता सामने आए हैं, जिन्हें पीछे की पंक्ति से निकालकर अचानक प्रमुख पद सौंपा गया। भाजपा के वर्तमान 14 राज्यों में मुख्यमंत्री पद की स्थिति का विश्लेषण बताता है कि शपथ ग्रहण के समय केवल पांच मुख्यमंत्री 55 वर्ष से अधिक उम्र के थे। त्रिपुरा के माणिक साहा (70), गुजरात के भूपेंद्र पटेल (60), छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय (59) जैसे चेहरे शामिल हैं। अटल-आडवाणी के दौर में भी युवा नेताओं को भाजपा में तरजीह मिली थी। नितिन नवीन के चुनाव में सबसे अधिक पीएम मोदी की चली है। मोदी ने इससे एक मजबूत संदेश संघ और पार्टी को दिया है। जब यह तय करने की बात आएगी कि कौन किस पद पर रहेगा तो वह ही अंतिम अर्थारिटी होंगे। किसी लॉबी का दवाब काम नहीं आएगा। पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह की जोड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी जिस पर RSS का मुहर भी हो और वह अन्य किसी वरिष्ठ नेता के करीब भी न हो। नितिन नवीन इस कसौटी पर खरे उतरते हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

		
अटल बिहारी वाजपेयी संस्थापक अध्यक्ष (1980-1986)	लाल कृष्ण आडवाणी 1986-1990, 1993-1998, 2004-2005	डॉ. मुरली मनोहर जोशी 1991-1993
		
कुशा भाऊ ठाकरे 1998-2000	बंगारु लक्ष्मण 2000-2001	के. जाना कृष्णमूर्ति 2001-2002
		
वेंकैया नायडू 2002-2004	राजनाथ सिंह 2005-2009, 2013-2014	नितिन गडकरी 2010-2013
		
अमित शाह 2014-2017, 2017-2020	जगत प्रकाश नड्डा 2020-अवतक	नितिन नवीन 2026 (राष्ट्रीय अध्यक्ष)



अपॉइंटमेंट, ऑटोमोबिल, प्रॉपर्टी, मैट्रिमोनी, नौकरी, वैवाहिक सेवाएं, नाम परिवर्तन या किसी भी कैटेगरी का विज्ञापन, अब चंद मिनटों में करें, कभी भी और कहीं से भी

पंचायत ग्राउन्ड जीरो से (दैनिक अखबार)

के क्लासिफाइड विज्ञापनों की फ़ोन से करें बुकिंग।

Panchayat Ground Zero se

9918336644, 9415051730



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

**DOWN
LOAD
करें**

R.N.I.NO: UPHIN/2023/87530

पंचायत ग्राउन्ड जीरो से

हिन्दी दैनिक अखबार

निष्पक्ष खबरों का नया अड्डा

ब्रेकिंग न्यूज
अब आपके मोबाइल पर
हर समय, हर समाचार

“पंचायत ग्राउंड जीरो से”
के मोबाइल एप को डाउनलोड करें..



**PANCHAYAT
GROUND ZERO SE**



[Download Now!](#)